A Daily News Magazine
इंदौर
मंगलवार, 29 अप्रैल, 2025
इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित
वर्ष 10 अंक 199, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

पाकिस्तान को दबाव में रखें, फिर सटीक और लगातार हमला करें

ले.जन. एच.एस. पनाग (रि.)

कश्मीर के पहलगाम से दो किमी दक्षिण-पश्चिम में स्थित बैसारन घाटी में, जिसे 'मिनी स्विट्जरलैंड' कहा जाता है, कायरतापूर्ण आतंकी हमले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। जम्मू-कश्मीर में उठी अलगाववादी लहर के 36 साल के इतिहास में सैलानियों पर यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। इसमें 28 लोग मारे गए हैं और 17 लोग घायल हुए हैं।

धार्मिक दृष्टि से देखें तो पवित्र अमरनाथ गुफा के तीर्थयात्रियों पर पहले भी हमले किए जाते रहे हैं, लेकिन सैलानियों को बख्श दिया जाता रहा है क्योंकि इससे कश्मीरियों की आजीविका प्रभावित होती। साफ है कि इस बार आतंकवादी और पाकिस्तान एक संदेश देना चाहता था। और यह संदेश बड़े दुस्साहस और बड़ी क्रूरता के साथ दिया गया है।

हमले के लिए समय का चुनाव भी प्रतीकात्मक है–अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस भारत के दौरे पर आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हुए थे। जाहिर है, सुरक्षा के मामले में गंभीर चूक हुई है।

इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाना चाहिए कि पाकिस्तान भले ही आर्थिक मुसीबतों से घिरा है लेकिन जम्मू-कश्मीर में छद्मयुद्ध छेड़ने की उसकी क्षमता घटी नहीं है, न ही जम्मू-कश्मीर को हड़पने के लिए भारत को हजारों घाव देने की उसकी रणनीति में कोई बदलाव आया है। जो रणनीतिक माहौल है, जम्मू-कश्मीर की जनता का जो मूड है, और घुसपैठ रोकने तथा आतंकवादियों का मुक़ाबला करने की दृष्टि से सुरक्षाबालों की जिस तरह की तैनाती है, उन सबके मद्देनजर पाकिस्तान आज सामरिक दृष्टि से आतंकवादियों के प्रवाह को अपने नियंत्रण में रखने की स्थिति में है।

अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के बाद घाटी में बढ़ी सुरक्षा, रजौरी-जम्मू-डोडा क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी ग्रिड की कमजोरी, और जम्मू तथा पठानकोट के बीच खुली अंतरराष्ट्रीय सीमा के कारण पीर पंजाल के दक्षिण के क्षेत्र पर ज्यादा ज़ोर देना कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। शहरी इलाकों में और सड़कों पर सुरक्षाबालों की ज्यादा तैनाती के कारण आतंकवादियों ने जंगल और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों की ओर रुख कर लिया है। आतंकवादियों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन वे बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त हैं, और बेहतर हथियारों तथा साजोसामान से लैस हैं।

पहलगाम में हमला कई कारणों से किया गया। एक तो पाकिस्तान कश्मीर घाटी में अपनी मौजूदगी जताना चाहता था, ताकि वहां के लोग कहीं बेहतर विकल्प को न चुन लें। भारत 'नया कश्मीर' का जो सपना दिखा रहा है उसे भी वह तोड़ना चाहता है। केवल गैर-मुसलमानों को ही निशाना बनाने का मकसद देश के बाकी हिस्से में दक्षिणपंथी दबाव झेल रहे दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ हिंसा को भड़काना, और जम्मू-कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यकों के अंदर अलगावादी भावना पैदा करना है। पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है कि वह अफगानिस्तान के तालिबान, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और बलूच आतंकवादी गुटों की मिलीभगत से बलूचिस्तान में आतंकवाद को भड़का रहा है। बोलन सुरंग घेराबंदी, जिसमें बड़ी संख्या में सैनिक और उनके परिजन मारे गए थे, पाकिस्तानी फौज के लिए बड़ा झटका था। इसलिए उसने बदले की कार्रवाई करने का आह्वान किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी फौज की अलोकप्रियता बढ़ रही है।

इन तथ्यों के मद्देनजर, बड़े आतंकी हमले का पूर्वानुमान लगाया जाना चाहिए था। पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स की आतंकवाद विरोधी ग्रिड की मौजूदगी सड़कों और शहरी इलाकों में ही सीमित है। आतंकवादियों का दबदबा जंगली क्षेत्रों और पहाड़ों में है, जहां वे स्थानीय लोगों पर ज़ोर-जबरदस्ती करके उनसे मदद हासिल करते हैं। जिस क्षेत्र में रोज करीब 1500 सैलानी आते हैं, जिन्हें किसी पुलिस या सुरक्षाबल की सुरक्षा नहीं हासिल है।

नव-राष्ट्रवाद की घुट्टी पी चुका, आक्रोश से भरा देश खून का प्यासा नजर आ रहा है। लेकिन सरकार को जन भावना के दबाव में हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। याद रहे कि पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न देश है और उसने परमाणु युद्ध से नीचे के स्तर के सीमित युद्ध करने की पर्याप्त पारंपरिक क्षमता हासिल कर ली है। मिसाइल, ड्रोन, हवाई या समुद्री ताकत से जुड़ी टेक्नोलॉजी के मामले में भारत इतनी बड़ी बढ़त नहीं रखता है, ताकि वह बदला लेने के लिए जोरदार सर्जिकल स्ट्राइक कर सके। पाकिस्तान जैसे को तैसा जवाब देने की क्षमता रखता है, इसलिए हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। फौरी जवाबी कार्रवाई गोलाबारी, स्पेशल फोर्स के हमले, हवाई/ड्रोन/मिसाइल से हमले एलओसी के पार दुश्मन की चुनिंदा चौकियों पर कब्जे के लिए छोटे स्तर के ऑपरेशन के रूप में किए जा सकते हैं। इस तरह के ऑपरेशन सामरिक कार्रवाई के दायरे में आते हैं, जो बड़े युद्ध में नहीं बदलते। लेकिन इनके जवाब में वैसी ही कार्रवाई हो सकती है।

अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार मुरीदके और बहावलपुर में लश्करे तय्यबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे गुटों के अड्डों को निशाना बनाना रणनीति के दायरे में आएगा और इसका नतीजा एक सीमित युद्ध के रूप में निकल सकता है। लेकिन इस तरह की कार्रवाई तभी की जानी चाहिए जब दुश्मन को इसकी आशंका भी न हो। यह फौरी जवाबी कार्रवाई का एक रूप नहीं है। इस विकल्प को अगर जम्मू-कश्मीर तक सीमित किया जाए तो यह परमाणु हथियार के प्रयोग से पहले का एक बड़ा विकल्प हो सकता है। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की ओर से जो छद्मयुद्ध जारी है वह, और पहलगाम में किए गए हमले के पैमाने पर किया गया आतंकवादी हमला इस तरह के विकल्प को चुनने का पर्याप्त अंतरराष्ट्रीय औचित्य प्रदान करता है। इसे अंजाम देने का सबसे बढ़िया समय तब होगा जब पहाड़ों पर बर्फ पिघल चुकी हो। अगर इस विकल्प पर अमल किया जाता है तो जम्मू-कश्मीर के बाहर के क्षेत्र में बचाव की रणनीतिक मुद्रा अपनाना बुद्धिमानी होगी। और दुनिया को इस बारे में बताया जा सकता है। एलओसी को 10 दिन में 10-15 किमी पीछे धकेला जा सकता है ताकि परमाणु हथियारों का प्रयोग शुरू होने से पहले उसके रणनीतिक लक्ष्यों को खतरे में डाला जा सके। घुसपैठ की सुविधा देने वाले सभी अड्डों पर कब्जा किया जा सकता है। यह पाकिस्तान को अमन की मांग करने को बाध्य कर सकता है क्योंकि तब चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरीडोर खतरे में आ जाएगा।

हमें अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए जन भावना के दबाव में हड़बड़ी में युद्ध का बिगुल नहीं बजाना चाहिए। भारत सोची-समझी रणनीति को करीने से लागू करते हुए पाकिस्तान को दहशत में रखे ताकि भारत हमले की पहल कर सके, निर्णायक हमला कर सके और बार-बार हमला कर सके जब तक कि वह अपना राजनीतिक लक्ष्य नहीं हासिल कर लेता।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

मुख्यमंत्री कल करेंगे श्रमिक परिवारों को राशि वितरित

अनुग्रह सहायता योजना के 27,523 प्रकरणों में 600 करोड़ रूपये की राशि की जाएगी अंतरित

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 30 अप्रैल को धार जिले के उमरबन में संबल योजना में अनुग्रह सहायता के 27 हजार 523 प्रकरणों में राशि रूपये 600 करोड़ सिंगल क्लिक से वितरित करेंगे। कार्यक्रम में श्रम व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल एवं स्थानीय जन प्रतिनिधि, हितग्राही उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना, प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसमें अनुग्रह सहायता योजना के अंतर्गत दुघर्टना में मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये एवं सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये प्रदान किये जाते हैं। इसी प्रकार स्थायी अपंगता पर 2 लाख रूपये एवं आंशिक स्थायी अपंगता पर 01 लाख रूपये तथा अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5 हजार रूपये प्रदान किये जाते हैं। संबल योजना में जहाँ एक ओर महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता के रूप में 16 हजार रूपये दिये जाते हैं तो वहीं दूसरी ओर श्रमिकों के बच्चों को महाविद्यालय शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा में शिक्षा हेतु सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। नीति आयोग की पहल पर प्रदेश के गिग एवं प्लेटफार्म वर्कर्स को भी संबल योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाकर इनका पंजीयन प्रारम्भ किया गया है एवं इन्हें भी संबल योजना के अंतर्गत समस्त लाभ प्रदान किये जा रहे हैं। संबल हितग्राहियों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची भी प्राप्त होती है जिससे वे केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा रियायती दरों पर राशन प्राप्त कर रहे हैं। संबल योजना प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसमें श्रमिक को जन्म से लेकर मृत्यु तक आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के लाखों निर्माण श्रमिकों के लिये भी निर्माण मंडल के माध्यम से कई योजनायें संचालित की जाती हैं। इनमें निर्माण श्रमिकों की मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता तथा स्थायी एवं आंशिक अपंगता पर सहायता भी सम्मिलित है। सभी संबल हितग्राहियों को आयुष्मान भारत निरामयम योजना अंतर्गत पात्र श्रेणी में चिन्हित किया गया है, अब वे भी 5 लाख रूपये वार्षिक निःशुल्क चिकित्सा प्राप्त कर रहे है। प्रदेश सरकार द्वारा योजना प्रारंभ से अब तक 01 करोड़ 75 लाख श्रमिकों का संबल योजना के अंतर्गत पंजीयन किया गया है, पंजीयन प्रक्रिया जारी है। संबल योजना के अंतर्गत वर्ष 2018 से वर्तमान तक कुल 6 लाख 81 हजार से अधिक प्रकरणों में राशि रूपये 6 हजार 432 करोड़ से अधिक के हितलाभ का वितरण किया जा चुका है।

यूपी से चुन-चुन कर बाहर किए गए पाकिस्तानी

सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ही कर रहे मॉनीटरिंग

लखनऊ (एजेंसी)। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश से पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश और पल-पल मॉनीटरिंग का नतीजा है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, जहां 24 घंटे के अंदर प्रदेश में रह रहे शत-प्रतिशत पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर कर दिया गया है। वहीं, अंतिम बचे एक पाकिस्तानी नागरिक को बुधवार को वापस भेज दिया जाएगा। पुलिस विभाग और खुफिया एजेंसी लगातार उस पर नजर बनाए हुए है। आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा ऐक्शन लेते हुए कई अहम निर्णय लिया। इस दौरान केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी करते हुए पाकिस्तानी नागरिकों को वापस उनके देश भेजने के निर्देश दिए। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। सीएम योगी ने बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि प्रदेश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल प्रदेश से बाहर करें।

सुप्रभात

इतना तेज़ घाम क्यों है
फिर एक पहलगाम क्यों है
अल्लाह तो माबूद है ही
इस पर कत्लेआम क्यों है
रसूल राम भी मुहम्मद के सिवा
बरपा एक कोहराम क्यों है
दीन का नाम और ये खूँरेजी
मौत का एहतेमाम क्यों है
गुल नबातात की रुत में
आज दहशत तमाम क्यों है
बेटे दूर गये न लौटेंगे अब
दिल में उम्मीदे पयाम क्यों है
दहशती पॉच पचास ही होंगे
कौम से इंतकाम क्यों है
चिड़िया भी बोलती नहीं है कुछ
आज यूँ खामोश शाम क्यों है।

- विवेक चतुर्वेदी

जल गंगा संवर्धन अभियान

उद्यानिकी विभाग की 'पानी चौपाल' बनी मुख्य आकर्षण

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर प्रदेश में 30 मार्च से प्रारंभ किये गये जल गंगा संवर्धन अभियान में उद्यानिकी विभाग द्वारा गाँव-गाँव में आयोजित की जा रही 'पानी चौपाल' आकर्षण का प्रमुख केन्द्र बन गई है। 'पानी चौपाल' में मैदानी अमले द्वारा गाँव के किसानों को जल संरक्षण के साथ, कम पानी से होनी वाली फसलों, कृषि के साथ उद्यानिकी फसलों को जोड़कर अधिक लाभ कमाने और नवीन उद्यानिकी तकनीकियों की समझाइश दी जा रही है। इसके साथ ही अभियान के दौरान ही फलोद्यान, ड्रिप लाइन, प्लास्टिक मलचिंग, सब्जी क्षेत्र, मसाला क्षेत्र, पुष्प क्षेत्र विस्तार योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये उद्यानिकी विभाग के ऑनलाइन पोर्टल से पंजीयन भी कराया जा रहा है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 'पर ड्रॉप-मोर क्रॉप' अंतर्गत 13 हजार 500 कृषकों को 76.68 करोड़ रूपये की लागत स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। लगभग 5 हजार हेक्टेयर में फलदार पौधों का रोपण, सभी विकासखंड में उपलब्ध जल से सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उचित प्रबंधन पर कार्यशालाओं का आयोजन करने तथा अभियान के लिये 25 लाख से अधिक फलदार पौधे उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये 'पानी चौपाल' में ही किसानों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी भी प्रदान की जा रही है। गुना जिले के गुना विकासखंड ग्राम

- **योजनाओं का ऑनलाइन पंजीयन भी अब चौपाल पर ही हो रहा**

अकावदा में, विकासखंड चाचौड़ा की ग्राम पंचायत उकविदा, शिवपुर, टीकमगढ़ जिले के विकासखंड जतारा के नतोवली ग्राम पंचायत सेवार, रतलाम जिले के सैलाना विकासखंड के ग्राम सलवानिया और ग्राम सोहौला, छतरपुर जिले के लवकुश नगर विकासखंड के ग्राम में, अशोक नगर जिले के विकासखंड मुगांवली की शासकीय संजय निकुंज गोपालिया में, नर्मदापुरम के विकासखंड माखननगर, मैहर जिले के विकासखंड मुख्यालय के ग्रामों में, सिवनी जिले के विकासखंड केवलारी के ग्राम खैराजी सहित प्रदेश के सेकड़ों ग्रामों में पानी चौपालों का आयोजन लगातार जारी है।

17 पाक यू-ट्यूब चैनल किए गए बैन

नई दिल्ली (एजेंसी)। पहलगाम अटैक की रिपोर्टिंग को लेकर भारत ने सोमवार को 17 पाकिस्तानी यू-ट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया है। इनमें क्रिकेटर शोएब अख्तर, डॉन न्यूज, समा टीवी और जिओ न्यूज शामिल हैं। सरकार का कहना है कि ये चैनल्स भारत और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ झूठी और भ्रामक खबरें चला रहे हैं। इनको भी चेतावनी दी गई है। पहलगाम हमले की रिपोर्टिंग के दौरान चैनल आतंकवादियों को उग्रवादी बता रहा था। सरकार ने यह कार्रवाई गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद की है। उधर, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में आज बुलाए गए विशेष सत्र में पहलगाम में मारे गए टूरिस्टों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ के बीच एक अहम मीटिंग हुई।

63 हजार करोड़ में मिलेंगे 26 राफेल मरीन विमान

- **भारत और फ्रांस के बीच 'राफेल' डील हुई पक्की**

पहला फाइटर जेट विमान 2028 में भारत पहुंचेगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत, फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन विमानों की डील सोमवार को नई दिल्ली साइन हो गई। भारत की तरफ से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने डील पर साइन किए। डील के तहत भारत, फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। ये विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के साथ ये डील करीब 63,000 करोड़ रुपए में हो रही है। हथियारों की खरीद के मामले में यह फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है। विमानों की खरीद को 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में मंजूरी मिली थी। यह मीटिंग पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद बुलाई गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन विमानों की डिलीवरी 2028-29 में शुरू होगी और 2031-32 तक सभी विमान भारत पहुंच जाएंगे। भारत और फ्रांस की सरकार के बीच सोमवार को राफेल डील पर हस्ताक्षर किया गया। राफेल से जुड़े समझौतों पर नई दिल्ली में साइन किया गया। फ्रांस के रक्षा मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत में शामिल हुए। नौसेना के लिए मरीन (एम) श्रेणी के राफेल लड़ाकू विमान खरीदे जा रहे हैं। भारतीय नौसेना को कुल 26 राफेल-एम विमानों की आपूर्ति की जाएगी।

पीएम मोदी-राजनाथ की मीटिंग के बीच डील साइन- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने फ्रांस से 26 राफेल-एम लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी। हाल ही में मिली इस मंजूरी के बाद अब यह डील पर मुहर लगी है। इस डील से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यहां दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक गंभीर वार्ता हुई है। राफेल की डील पर हस्ताक्षर के बाद भारतीय नौसेना और ताकतवर होगी।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 22 °c
न्यूनतम 16°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ मंगलवार, 29 अप्रैल 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

भारत के 3 दुश्मनों ने मिलाया पाकिस्तान के साथ हाथ

युद्ध की स्थिति में तीन देशों ने किया समर्थन देने का ऐलान

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत से तनाव के बीच तीन देशों ने इस्लामाबाद का समर्थन किया है। चीन और तुर्की के बाद अब अजरबैजान ने भी पाकिस्तान का साथ देने की घोषणा की है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद आशंका है कि भारत और पाकिस्तान जंग में जा सकते हैं। जिसको लेकर एक तरफ जहां ईरान और सऊदी अरब ने तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के नेताओं से बात की है, वहीं चीन और तुर्की को लेकर रिपोर्ट है कि उसने पाकिस्तान को घातक हथियार मुहैया

करवाए हैं। इस्लामाबाद को हथियार पहुंचाने के अलावा चीन ने रविवार को पाकिस्तान को उसकी संप्रभुता और सुरक्षा हितों की रक्षा करने में अपना समर्थन देने की घोषणा की है। चीनी सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह संघर्ष भारत और पाकिस्तान के मौलिक हितों में नहीं है, न ही यह क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए अनुकूल है। उम्मीद है कि दोनों पक्ष संयम बरतेंगे, एक-दूसरे से मिलकर काम करेंगे और स्थिति को शांत करने में मदद करेंगे। इससे पहले पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार, जो देश के विदेश मंत्री भी हैं, उन्होंने रविवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी को फोन किया था। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के मुताबिक इशाक डार ने भारत की एकतरफा और अवैध कार्रवाइयों के खिलाफ विरोध किया है।

पंजाब-पाक बॉर्डर पर अक्टूबर तक लगेंगी एंटी ड्रोन तकनीक

ड्रग तस्करी में शामिल 31 हवाला ऑपरेटर गिरफ्तार

चंडीगढ़ (एजेंसी)। पंजाब को 31 मई तक नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस ने पूरी योजना बना ली है। सभी जिलों के एसएसपी और सीपी को निर्देश दिए गए हैं। उन्हें तय समय में इस दिशा में कार्रवाई करने को कहा गया है। तय तिथि के बाद पूरे अभियान की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान जिन अधिकारियों का काम अच्छा होगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। वहीं, जिनका

काम मानकों के मुताबिक नहीं होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह दावा पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने किया है। उन्होंने कहा कि भारत-पाक सीमा पर एंटी ड्रोन तकनीक लगाने का काम चल रहा है। इसका ट्रायल हो चुका है और हमारे अधिकारी गृह मंत्रालय (एमएचए) के संपर्क में हैं। सितंबर-अक्टूबर तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। वहीं, 30 एनडीपीएस मामलों के लिए कोर्ट बनाई जाएगी। इस पर राज्य सरकार 22.8 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं, नशा तस्करी में शामिल 31 हवाला ऑपरेटरों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है।

बाबा केदार चले अपने धाम, 2 मई को खुलेंगे कपाट

● बैंड की धुन के बीच पंचमुखी मूर्ति संग पैदल रवाना हुए श्रद्धालु

रुद्रप्रयाग (एजेंसी)। श्री केदारनाथ धाम के कपाट आगामी दो मई को श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहे हैं। धाम के कपाटोत्सव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही है। वहीं सोमवार को सेना के बैंड की भक्तिमय धुन के साथ बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली ने रावल की अगुवाई में अपने धाम के लिए प्रस्थान किया। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव मूर्ति को पंचस्नान करवाया गया।

इसके बाद पंचमुखी उत्सव मूर्ति को डोली में विराजमान कर फूलों से सजाया गया। वहीं, बाबा के शीतकालीन प्रवास स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ को भी फूलों से भव्यरूप से सजाया गया था। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदार बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। भारतीय सेना के

बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ रावल भीमाशंकर लिंग और बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने बाबा केदार की डोली को श्री केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान कराया। विजय प्रसाद थपलियाल ने इस अवसर पर तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली विभिन्न स्थानों मंदिर मार्ग उखीमठ, संसारी, विद्यापीठ, गुप्तकाशी बाजार में भक्तों को दर्शन देते हुए प्रथम पड़ाव विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंचेगी। पंचमुखी मूर्ति अपने प्रथम पड़ाव श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में रात्रि विश्राम के लिए रुकेगी। इसके बाद 29 अप्रैल को गुप्तकाशी से दूसरे पड़ाव फाटा के लिए प्रस्थान करेगी और यहां रात्रि विश्राम करेगी।

30 अप्रैल को फाटा से श्री गौरीमाता मंदिर गौरीकुंड प्रस्थान एवं रात्रि विश्राम होगा। बताया कि 1 मई को गौरीकुंड से श्री केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान किया जाएगा और शाम तक पंचमुखी डोली श्री केदारनाथ धाम पहुंच जायेगी। 2 मई को सुबह सात बजे श्री केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। बीकेटीसी मीडिया प्रभारी हरीश गौड़ ने बताया कि श्री केदारनाथ धाम में भी मंदिर समिति के अग्रिम दल ने यात्रा पूर्व तैयारियां पूरी कर ली है।

17 पाकिस्तानी यू-ट्यूब चैनल पर चली कैंची

नई दिल्ली (एजेंसी)। पहलगाम अटैक की रिपोर्टिंग को लेकर भारत ने सोमवार को 17 पाकिस्तानी यू-ट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया है। इनमें क्रिकेटर शोएब अख्तर, डॉन न्यूज, समा टीवी और जिओ न्यूज शामिल हैं। सरकार का कहना है कि ये चैनल्स भारत और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ झूठी और भ्रामक खबरें चला रहे हैं। इनको भी चेतावनी दी गई है। पहलगाम हमले की रिपोर्टिंग के दौरान चैनल आतंकवादियों को उग्रवादी बता रहा था। सरकार ने यह कार्रवाई गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद की है। उधर, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में आज बुलाए गए विशेष सत्र में पहलगाम में मारे गए टूरिस्टों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ के बीच एक अहम मीटिंग हुई। 40 मिनट तक चली इस मीटिंग में राजनाथ ने प्रधानमंत्री को पहलगाम अटैक पर विस्तार से जानकारी दी। आज रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक भी होने वाली है। इस बीच, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 15 ठिकानों पर रेड की है। कार्रवाई आतंकवादियों के ठिकानों पर की गई है।

तेलंगाना की चर्चित आईएएस अफसर स्मिता सभरवाल का ट्रांसफर

● हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास जंगल काटने का किया था भारी विरोध ● एआई जनरेटेड कार्टून शेयर किया था, रेवंत सरकार की हुई किरकिरी

हैदराबाद (एजेंसी)। सोशल मीडिया पर एआई जनरेटेड फोटो शेयर करके विवादों में आई तेलंगाना कैडर की आईएएस अधिकारी स्मिता सभरवाल का ट्रांसफर कर दिया है। 31 मार्च 2025 को स्मिता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एआई की जिबली फोटो शेयर की थी। जिसमें 1 मोर और 2 हिरण खड़े थे, जिनकी तरफ बुलडोजर तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्मिता ने यह तस्वीर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास कांचा गाचीबोवली में 400 एकड़ जमीन पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के विरोध में किया था। हैदराबाद यूनिवर्सिटी छात्रसंघ, पेड़ों की कटाई और वन्यजीवों के लिए खतरे को लेकर इसका विरोध कर रहा था। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। स्मिता के अलावा 20 अन्य अधिकारियों का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। स्मिता सभरवाल का जन्म 19 जून 1977 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ था। सभरवाल साल 2000 में चौथी रैंक लगाकर यूपीएससी टॉपर बनीं थीं। आईएएस की ट्रेनिंग के बाद उन्हें तेलंगाना कैडर मिला था। स्मिता सभरवाल वर्तमान में युवा उन्नति, पर्यटन और संस्कृति की मुख्य सचिव हैं। साथ ही वो पुरातत्व विभाग की निदेशक भी हैं। अब उन्हें तेलंगाना के वित्त आयोग में सदस्य सचिव नियुक्त कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट बोला- तेलंगाना में पेड़ कटाई की स्थिति गंभीर

सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास की जमीन पर किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था- तेलंगाना सरकार को जमीन पर पेड़ों की सुरक्षा के अलावा कोई गतिविधि नहीं करनी चाहिए। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राज्य में पेड़ों की कटाई को बहुत गंभीर बताया। पीठ ने कहा था- तेलंगाना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट इसकी खतरनाक तस्वीर दिखाती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं। इसके अलावा पीठ ने तेलंगाना के मुख्य सचिव से यूनिवर्सिटी के पास की जमीन पर पेड़ काटकर काम शुरू करने की जल्दी पर जवाब मांगा है। साथ ही पूछा है कि क्या राज्य ने इस तरह की गतिविधियों (पेड़ों की कटाई) के लिए पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का असेसमेंट सार्टिफिकेट लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को यूनिवर्सिटी के पास की 400 एकड़ जमीन पर पेड़ों की कटाई का संज्ञान लिया था। कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को साइट का दौरा कर रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया था।

रेलवे एग्जाम्स में मंगलसूत्र-जनेऊ अब नहीं उतारने होंगे

● भारी विवाद के बीच रेल राज्य मंत्री ने बोर्ड को दिया आदेश

कर्नाटक के डिप्टी सीएम भी बोले- जांच करें पर हटाए नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने रेलवे भर्ती बोर्ड को धार्मिक चिन्हों को उतारने वाले नियम को हटाने का आदेश दिया है। जिसमें परीक्षा देने

वाले छात्रों के कान की बाली, मंगलसूत्र, जनेऊ उतरवा दिए जाते थे। भाजपा सांसद बृजेश चौटा ने सोमवार को एक्स पर यह जानकारी दी। चौटा ने रेलवे भर्ती बोर्ड के पेरा-मेडिकल के एडमिट कार्ड का फोटो भी शेयर किया। जिसमें लिखा था कि मंगलसूत्र और जनेऊ जैसे धार्मिक प्रतीक और आभूषण पहन कर परीक्षा में नही आ सकते। चौटा ने बताया कि केंद्रीय मंत्री सोमन्ना ने अधिकारियों से कहा है कि वे ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हों जिसमें छात्रों को धार्मिक प्रतीकों और आभूषणों को हटाने की जरूरत हो। कर्नाटक सरकार ने भी इस नियम पर आपत्ति जताई थी। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा- मंगलसूत्र या जनेऊ धार्मिक चीज होती है, आवश्यकता पड़ने पर इसकी जांच कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हटाना सही नहीं है। कर्नाटक के बीदर जिले के साई स्पूर्थी पीयू कॉलेज में 17 अप्रैल को एक स्टूडेंट ने जनेऊ उतारने से मना किया तो उसे एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया था। 19 अप्रैल को मामला सुर्खियों में आया और इस पर विवाद हुआ।

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता मामले में सुप्रीम कोर्ट हो गई सख्त

कहा-ये गंभीर मुद्दा, सरकार ऐक्शन ले, केंद्र बोला-नए नियमों पर काम जारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को ऑनलाइन अश्लील कंटेंट की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार और 9 ओटीटी-सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि याचिका एक गंभीर चिंता पैदा करती है। केंद्र को इस पर कुछ कदम उठाने की जरूरत है। यह मामला कार्यपालिका या विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे भी हम पर आरोप हैं कि हम कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल देते हैं। फिर भी हम नोटिस जारी कर रहे हैं। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट को लेकर कुछ रेगुलेशन पहले से मौजूद हैं। सरकार और नए नियम लागू करने पर विचार कर रही है। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन पेश हुए। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार से ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट पर रोक लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि ऐसी सामग्री युवाओं और समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 21 अप्रैल को इसी याचिका पर सुनवाई की थी। तब भी कोर्ट ने कहा था कि मुद्दा एक नीतिगत मामला है।

देश पहले, धर्म या पार्टी बाद में

हम सरकार के साथ

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए देश सबसे पहले है। धर्म-जाति या पार्टी का महत्व बाद में है। खड़गे ने कहा कि देश के लिए हम सभी को एकता दिखानी

● जयपुर में पहलगाम हमले को लेकर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे

होगी। उन्होंने इस दौरान एक बार फिर कहा कि मोदी सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद होने चाहिए थे। हालांकि खड़गे ने यह भी कहा कि सरकार इस हमले के बाद जो भी कदम उठाएगी, कांग्रेस पार्टी राष्ट्र हित में उसके साथ खड़ी होगी। जयपुर में संविधान बचाओ रैली के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मैंने बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि प्रधानमंत्री को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी

चाहिए, क्योंकि जब देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचे तो हम सभी को एकजुट रहना चाहिए। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, हम चाहते थे, इस बैठक में प्रधानमंत्री अपने प्लान के बारे में बताएं और लोगों के सुझाव भी लें। इसके अलावा, हमने मीटिंग भी बुलाई, जिसमें हमने तय किया था कि हम सभी सरकार के साथ हैं। कांग्रेस प्रमुख ने कहा, हमने सर्वदलीय बैठक में भी कहा था कि इस कठिन समय में हम सरकार द्वारा उठाए जाने वाले किसी भी कदम में उनके साथ हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर जाकर पहलगाम हमले के घायलों से मुलाकात और बातचीत की लेकिन नरेंद्र मोदी न तो सर्वदलीय बैठक में पहुंचे और न ही कश्मीर गए। पीएम मोदी पर हमलावर होते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि देश सबसे पहले है। देश के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए।

पहलगाम अटैक पर सीएम उमर अब्दुल्ला का भावुक संबोधन

● सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी थी, मृतकों के परिजनों से क्या कहूं, माफी के लिए शब्द नहीं

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सोमवार को पहलगाम अटैक में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा- मेजबान होने के नाते मैं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। इन लोगों के परिजन से मैं कैसे माफी मांगू। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उमर ने कहा- जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सीएम और टूरिज्म मिनिस्टर होने के नाते मैंने इन्हें बुलाया था। मेजबान होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी कि इन्हें सुरक्षित भेजूं, नहीं भेज पाया। उमर ने कहा- उन बच्चों से क्या कहता, जिन्होंने अपने वालिद को खून में लिपटा हुआ देखा।

पहलगाम हमले के बाद घाटी में नए मिशन की तैयारी

टूरिस्ट के मोर्चे पर उमर अब्दुल्ला के साथ खड़ी हुई बीजेपी

नई दिल्ली (एजेंसी)। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पहलगाम में बेगुनाह टूरिस्ट को निशाना बनाने के पीछे आतंकवादियों और उनके आकाओं का मकसद क्या था। वे किसी भी सूरत में केंद्र शासित प्रदेश की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यह बात भी उतनी ही सच है कि पहलगाम में जिस तरह से सैलानियों का धर्म पूछ कर, उनकी पहचान जानने के बाद एक के बाद 26 लोगों को चुन-चुनकर मौत की नींद सुलाया गया, उसी का नतीजा है कि कश्मीर में उस समय जो लोग थे, उनकी वापसी की लाइन लग गई। एयरलाइंस कंपनियों को अतिरिक्त सेवाएं देनी पड़ीं। होटल खाली हो गए, टूरिज्म पर निर्भर कारोबार ठप सा पड़ना शुरू गया और यहां तक की जरूरत के सामानों की डिमांड घटने की भी रिपोर्ट आने लगीं। इस हालात को देखते हुए जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो चिंता जताई है, उसमें बीजेपी उनके साथ पूरी तरह से खड़ी दिख रही है और हर हाल में कश्मीर के टूरिज्म को वही मुकाम दिलाने का संकल्प ले रही है, जो पिछले कुछ वर्षों में हासिल होने लगा है।

आबकारी घोटाला और फर्जी चालान का मामला

इंदौर में शराब कारोबारियों के ठिकानों पर ED के छापे, एक साथ 18 जगहों पर कार्रवाई

इंदौर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार सुबह इंदौर में एक साथ 18 जगहों पर छापे मारे। जिन जगहों पर छापे पड़े, उनमें ज्यादातर शराब कारोबारी शामिल हैं। ईडी की टीमों ने बसंत विहार कॉलोनी, तुलसी नगर और महालक्ष्मी नगर जैसे इलाकों में कार्रवाई की। सूत्रों के मुताबिक, ये कार्रवाई फर्जी बैंक चालान और आबकारी विभाग में हुए घोटाले को लेकर की गई है। यह घोटाला सबसे पहले साल 2018 में सामने आया था। आरोप है कि शराब कारोबारियों ने आबकारी विभाग के अफसरों के साथ मिलकर करोड़ों का घोटाला किया। माना जा रहा है कि घोटाले की रकम 100 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है।

कैसे हुआ घोटाला?

2015 से 2018 के बीच इंदौर जिला आबकारी कार्यालय में शराब गोदामों से शराब उठाने के लिए 194 फर्जी चालानों का इस्तेमाल किया गया। बैंक में हजारों रुपयों के छोटे चालान जमा कराए गए, लेकिन चालान में बाद में लाखों की रकम दिखाकर गोदामों से ज्यादा शराब उठा ली गई और दुकानों पर बेची गई। इस घोटाले की शिकायत मिलने के बाद ईडी ने 2024 में जांच शुरू की थी। जांच के लिए ईडी ने आबकारी विभाग और पुलिस से कई जरूरी दस्तावेज मांगे थे, जैसे कि शराब ठेकेदारों के बैंक अकाउंट का ब्योरा और विभाग की आंतरिक जांच रिपोर्ट।

पहले भी हुई थी कार्रवाई- इस घोटाले को लेकर 12 अगस्त 2017 को रावजी बाजार पुलिस स्टेशन में 14 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था। उस समय आबकारी विभाग के कई अफसरों को भी निलंबित किया गया था। निलंबित अधिकारियों में जिला आबकारी अधिकारी संजीव दुबे और अन्य कई अधिकारी शामिल थे। आरोप है कि आबकारी विभाग में इसके पहले तीन साल से फर्जी चालान जमा किए जा रहे थे।

आबकारी विभाग के अफसरों को हर 15 दिन में चालान को क्रॉस चेक करना (तौजी मिलान) होना था, लेकिन उन्होंने तीन साल तक ऐसा नहीं किया। इसकी वजह से उनकी साठगांठ साफ नजर आ रही थी। जिस वक्त यह शराब घोटाला हुआ था, उस वक्त जिला आबकारी कार्यालय में जिला आबकारी अधिकारी के पद पर संजीव दुबे नियुक्त थे। यही वजह रही कि आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त संजीव कुमार दुबे सहित छह अफसरों को निलंबित कर दिया था। निलंबित अधिकारियों में लसूड़िया आबकारी वेयरहाउस के प्रभारी डीएस सिसोदिया, महू वेयर हाउस के प्रभारी सुखनंदन पाठक, सब इंस्पेक्टर कौशल्या सबवानी, हेड क्लर्क धनराज सिंह परमार और अनमोल गुप्ता के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा 20 अन्य अधिकारियों के तबादले भी किए थे, जिनमें उपायुक्त विनोद रघुवंशी का नाम भी शामिल था।

इनके ठिकानों पर पड़े छापे

एमजी रोड समूह के अविनाश और विजय श्रीवास्तव, जीपीओ चौराहा समूह के राकेश जायसवाल, तोपखाना समूह के योगेंद्र जायसवाल, बायपास चौराहा देवगुराड़िया समूह के राहुल चौकसे, गवली पलासिया समूह के सूर्यप्रकाश अरोरा, गोपाल शिवहरे, लवकुश और प्रदीप जायसवाल के ठिकानों पर भी छापे मारे गए हैं।, बसंत विहार कॉलोनी में भी शराब कारोबारी के ठिकाने पर छोपमारी हुई। बसंत विहार कॉलोनी में भी शराब कारोबारी के ठिकाने पर छोपमारी हुई।

इंदौर की सड़कों पर लिखा- आतंकवादी पाकिस्तान मुर्दाबाद... झंडा भी बनाया

इंदौर। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के प्रति लोगों का आक्रोश और बढ़ता जा रहा है। इंदौर शहर में राजवाड़ा सहित तीन मुख्य मार्गों पर लोगों ने पाकिस्तान का झंडा बनाया और इसके साथ लिखा- आतंकवादी पाकिस्तान मुर्दाबाद। सड़क पर बना पाकिस्तान का झंडा लोग रौंदते हुए निकल रहे हैं।

पिग्स एंड पाकिस्तानी नाट अलाउड

इसके पहले इंदौर की 56 दुकान चौपाटी पर पाकिस्तान के विरोध में यहां के व्यापारियों ने एक पोस्टर लगाया था। यह पोस्टर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें लिखा था- पिग्स एंड पाकिस्तानी सिटिजंस नॉट अलाउड एट 56 दुकान। पोस्टर में पाकिस्तानी सेना के जनरल की वर्दी पहना एक पिग भी बना था।

हमले में इंदौर के सुशील नथानियल की हुई थी मौत

पहलगाम में हुए हमले में इंदौर के सुशील नथानियल की मौत हो गई थी। वे अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमने गए थे। आतंकियों ने उन्हें पकड़कर कलमा पढ़ने को कहा, जब उन्होंने कहा कि मैं क्रिश्चियन हूं, तो सीने में गोली मार दी। घटना के दौरान उनकी पत्नी और बेटी वहीं मौजूद थी। आतंकियों द्वारा की गई फायरिंग में उनकी बेटी के पैर में गोली लगी।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पीए पर हमला, ऑटो ड्रायवर से सामान रखने की बात पर हुई थी बहस

इंदौर। इंदौर के पलासिया इलाके में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पीए पर कैब ड्राइवर ने चाकू से हमला कर दिया। हमले की जानकारी लगने के बाद मंत्री समर्थक लोग अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की है। पुलिस के मुताबिक घटना साकेत नगर पलासिया इलाके की है। यहां रहने वाले बीजेपी नेता रवि विजयवर्गीय पर चाकू से हमला किया गया है। उन्हें अमरनेट अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रवि साकेत नगर में रहते हैं।

बेटे को स्टेशन जाना था- प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक रवि विजयवर्गीय के बेटे को बाहर जाना था। इसलिए उन्होंने टेक्सी बुलाई थी। सामान रखने की बात पर गाड़ी चालक से उनकी बहस हुई। इसके बाद उसने चाबी के छल्ले में लगा चाकू निकालकर रवि पर हमला कर दिया। बाद में रवि को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने उनके बयान के बाद आरोपी ड्रायवर पर केस दर्ज किया है। सूचना के बाद अस्पताल में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी पहुंचे हैं।

इंदौर में पहले बॉयफ्रेंड ने मिलने बुलाया, फिर चाकू से हमला कर हुआ फरार

इंदौर। इंदौर के हीरानगर इलाके में रविवार रात एक युवती के पहले बॉयफ्रेंड ने गुस्से में आकर उसके दूसरे बॉयफ्रेंड पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक, यह घटना युवती के अफेयर को लेकर हुई। युवती का पहले एक युवक से अफेयर था, लेकिन कुछ दिनों से उसने दूसरे युवक के साथ रिश्ते शुरू कर दिए थे, जिससे पहला बॉयफ्रेंड नाराज था। पुलिस ने बताया कि दिव्यांश (आरोपी) और मोहित (पीड़ित) के बीच झगड़ा तब हुआ जब दिव्यांश को युवती के बदलते रिश्ते का पता चला। दिव्यांश ने मोहित को मिलने के लिए बुलाया और फिर चाकू से पेट और पैर पर हमला कर दिया। घटना के वक्त दिव्यांश के दोस्त भी मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने मोहित को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी हमला करने के बाद फरार हो गया। हीरानगर पुलिस ने मोहित की शिकायत पर आरोपी दिव्यांश के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। मोहित का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

ट्रेन में पहलगाम के वीडियो देखने पर पीटा, घटना के 36 घंटे बाद जीआरपी पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

इंदौर। ट्रेन में सफर के दौरान पहलगाम का वीडियो देखने पर चंदन नगर के युवकों ने अनमोल परमार के साथ मारपीट की, उसे ट्रेन से धक्का देकर गिराने का भी प्रयास किया। मामले में पुलिस ने मेडिकल कराकर छोड़ दिया, जब घटना का वीडियो वायरल हुआ तो 36 घंटे बाद जीआरपी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। घटना शनिवार-रविवार की दरमियानी रात की है। अनमोल परमार रनिंग ट्रेन भोपाल से इंदौर का सफर कर रहा था। रात करीब 12 बजे अनमोल मोबाइल पर पहलगाम का वीडियो देखने लगा। इस पर दो युवकों ने आपत्ति लेते हुए कहा कि हमें देखकर ये वीडियो देख रहे हो। उन्होंने वीडियो को फर्जी बताया और अनमोल को धमकाया भी। जिसका विरोध करने पर युवकों ने मारपीट शुरू कर दी और कहा कि देशभक्ति ट्रेन के बाहर दिखाओ। अनमोल के कहने पर कि तुम भी इसी देश में रहते हो, आरोपियों ने कहा कि वे चंदन नगर में अपने अलग देश में रहते हैं। उनसे बचते हुए अनमोल ट्रेन के गेट पर पहुंचा, तो आरोपियों ने उसे धक्का देने की कोशिश की। तब अन्य यात्रियों ने अनमोल को बचाया।

एक वाट्सअप मैसेज से जमा किए डेढ़ लाख रुपए

इकलौते डॉक्टर बेटे को खो चुके बूढ़े माता-पिता की ऐसे की मदद, छलक उठे आंसू

इंदौर। इकलौते बेटे को खो चुके माता-पिता की आंख आज भी बेटे की याद में नम हो जाती हैं। मगर इस रविवार को उन दोनों की आंखें उस वक्त नम हो गईं, जब उनकी मदद को कुछ हाथ आगे बढ़े। परिवार के लोगों को जब इंदौर बुलाया गया और उन्हें एक लाख तीस हजार का चेक और 21 हजार रुपए नगद दिए तो उनकी आंखें भर आईं। जी हां ये वही परिवार है जिसने 27 दिसंबर 2024 को अपने इकलौते होम्योपैथी के डॉक्टर बेटे डॉ.सुनील साहू को हमेशा के लिए खो दिया। आज भी परिवार उस वक्त को याद कर रोने लगता है। हालांकि इस मामले में राजेंद्र नगर पुलिस ने डॉक्टर की पत्नी सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी जेल में है।

ऐसे बढ़े मदद के हाथ

हुआ यूं कि डॉ.सुनील साहू की मौत के चार महीने बाद डॉक्टर की बहन की शादी हुई। डॉक्टर का पूरा परिवार कुंभराज (गुना) में रहता है। आइडियल क्योर होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. बलराम गुप्ता ने बताया कि वे डॉ.सुनील की बहन की शादी में गए। यहां परिवार की स्थिति देख वे आश्चर्य में पड़ गए। क्योंकि उनके पिता छोटा

सी सब्जी की दुकान चलाते हैं। बेटे के जाने के बाद घर की स्थिति ठीक नहीं थी। उनकी स्थिति देख डॉ. बलराम ने वहीं पर परिवार की सात हजार रुपए देकर मदद की। शादी से लौटने के बाद वे अपने आप को रोक नहीं पाए। साथियों से बात की और उन्होंने डॉ.सुनील के परिवार की मदद की ठानी।

वाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया मैसेज

डॉ. बलराम गुप्ता ने बताया कि पिछले रविवार को उन्होंने एक मैसेज तैयार किया। जिसमें उन्होंने बताया कि वे परिवार की मदद करके आए हैं, लेकिन उनकी स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए हमें उनकी मदद करना चाहिए। अपने वाट्सएप ग्रुपों पर उन्होंने ये मैसेज सर्कुलेट किया। जैसे-जैसे ये मैसेज उनके ग्रुपों में अन्य डॉक्टरों ने पढ़ा वे मदद को आगे आने लगे।

चेक और नगद देकर की मदद

इंदौर के फूटी कोठी चौराहे के पास एसोसिएशन द्वारा हर रविवार को होम्योपैथी कैंप लगाया जाता है। कैंप में ही डॉ.सुनील के पिता जगदीश प्रसाद साहू अपनी पत्नी के साथ आए। यहां एसोसिएशन के अन्य सदस्यों के सामने उन्हें 1 लाख 30 हजार रुपए का चेक और 21 हजार रुपए नगद दिए गए। इस प्रकार उन्हें 1 लाख 51 हजार रुपए की आर्थिक मदद की गई है। डॉ.बलराम ने बताया कि 160 से ज्यादा लोगों ने इसमें मदद की है।

बुजुर्ग माता-पिता की नम हो गई आंखें

जब एसोएिशन के पदाधिकारियों ने बुजुर्ग माता-पिता की मदद की तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि बेटे के जाने के बाद एसोसिएशन के पदाधिकारी उनकी इस तरह से मदद करेंगे। डॉ. बलराम ने बताया कि अभी भी कई लोग मदद के लिए राशि भेज रहे हैं। आने वाले दिनों में जो राशि जमा होगी वह भी डॉ.सुनील के परिवार को सौंप दी जाएगी।

आईटी सेक्टर में ज्यादा निवेश के लिए इंदौर में लैंड बैंक बढ़ाएगी सरकार

इंदौर। इंदौर में आईटी से जुड़ी 80 से ज्यादा कंपनियां और स्टार्टअप है। आईटी विभाग अब तक चार आईटी पार्क बना चुका है। सिंहासा आईटी पार्क में रियायती दामों पर 28 कंपनियों को जमीन दी चुकी है। वहां कंपनियों ने संचालन भी शुरू कर दिया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा आईटी कंपनियां इंदौर में है। आईटी कॉन्क्लेव में भी चार कंपनियों को जमीन दी गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव के समक्ष भी यह मामला सामने आया कि इंदौर में निवेश के लिए लोग ज्यादा उत्सुक है, लेकिन जमीन कम पढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए लैंड बैंक में जमीन बढ़ाने के निर्देश दिए है। सरकारी जमीनों को भी उद्योगों के लिए दिया जा सकेगा। इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर ही चार बड़ी कंपनियों को पहले जमीन दी जा चुकी है।

80 से ज्यादा कंपनियां है इंदौर में- इंदौर में आईटी से जुड़ी 80 से ज्यादा कंपनियां और स्टार्टअप है। आईटी विभाग अब तक चार आईटी पार्क बना चुका है। सिंहासा आईटी पार्क में रियायती दामों पर 28 कंपनियों को जमीन दी चुकी है। वहां कंपनियों ने संचालन भी शुरू कर दिया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा आईटी कंपनियां इंदौर में है। आईटी कॉन्क्लेव में भी चार कंपनियों को जमीन दी गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव के समक्ष भी यह मामला सामने आया कि इंदौर में निवेश के लिए लोग ज्यादा उत्सुक है, लेकिन जमीन कम पढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए लैंड बैंक में जमीन बढ़ाने के निर्देश दिए है। सरकारी जमीनों को भी उद्योगों के लिए दिया जा सकेगा। इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर ही चार बड़ी कंपनियों को पहले जमीन दी जा चुकी है।

स्पेसटेक नीति भी बनेगी

प्रदेश सकरार स्पेसटेक नीति भी जल्दी लांच करने जा रही है,ताकि प्रदेश में अंतरिक्ष अनुसंधान हो सके और वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्यमों को प्रदेश में बढ़ावा मिल सके। इसके लिए भी कुछ कंपनियों ने सरकार से संपर्क किया है। इस कारण इससे जुड़ी नीति बनाने के निर्देश अफसरों को मुख्यमंत्री ने दिए है।

युवती ने बॉयफ्रेंड के खिलाफ दर्ज कराया केस, निजी फोटो सहेली और भाई को भेजे, शादी का दबाव डाला

इंदौर। इंदौर में एक निजी कंपनी में काम करने वाली 24 वर्षीय युवती ने अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ अश्लील फोटो और वीडियो बिना उसकी मर्जी के लेने, उन्हें वायरल करने और शादी के लिए दबाव डालने की शिकायत दर्ज कराई है। युवती के मुताबिक, आरोपी कमलजीत सचदेव उसके बचपन का दोस्त है और दोनों के बीच अफेयर भी था। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने कई बार युवती के साथ अंतरंग पलों की फोटो और वीडियो बिना उसकी जानकारी के ले लिए थे। हाल ही में, जब युवती ने शादी करने से इनकार किया, तो आरोपी ने इन फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद कमलजीत ने रुपयों की मांग भी शुरू कर दी थी। 21 अप्रैल को आरोपी ने युवती को धमकाते हुए कहा कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह इन फोटो और वीडियो को सबके सामने दिखा देगा। इस पर युवती डर के चलते चुप रही, लेकिन 25 मई को जब युवती के भाई ने उसे बताया कि कमलजीत ने उसकी फोटो उसे भेजी हैं, तो मामला सामने आया। इसके बाद युवती ने परिवार के साथ मिलकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

घुसपैठियों पर कार्रवाई की तैयारी, महापौर ने दी प्रशासन को चेतावनी, विधायक बोले हम खुद ढूंढेंगे

इंदौर। महापौर पुष्यमित्र भार्गव और विधायक गोलू शुक्ला ने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल डिपोर्ट करने की मांग की है। महापौर ने कहा कि फर्जी दस्तावेजों का पहले डिटेक्शन और डिलीशन कर डिपोर्टेशन किया जाए। जब नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू हुआ, तब 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात कही गई थी। लेकिन इसके अलावा देश में रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती समस्या पर भी विचार करना जरूरी है, जो आर्थिक और जनसांख्यिकी दृष्टि से बड़े शहरों में असंतुलन पैदा कर रहे हैं। हाल ही में पहलगाम में हुए हमले के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि अब सही समय है कि जो लोग बिना वीजा, अनुमति के इंदौर या मुंबई जैसे शहरों में रह रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। भार्गव ने कहा कि इंदौर में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों की मौजूदगी की जानकारी मिलती रही है, और अब इनकी पहचान कर तत्काल डिपोर्ट करने की आवश्यकता है।

डिटेक्ट, डिलीट और फिर डिपोर्ट

उन्होंने आगे कहा कि यदि उन्होंने किसी प्रकार का फर्जी पहचान पत्र बनाया है, तो उसे पहले डिटेक्ट

कर डिलीट किया जाए और फिर उन्हें डिपोर्ट किया जाए। भार्गव ने जोर देकर कहा कि ये घुसपैठिए न केवल देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि आर्थिक दबाव भी बढ़ा रहे हैं। उन्होंने यह भी मांग की कि इंदौर के तालाबों के आसपास अवैध रूप से बसे बांग्लादेशियों की जांच कर उन्हें भी जल्द से जल्द देश से बाहर भेजा जाए।

बंगाली कारीगरों को लेकर भी जताई चिंता

महापौर ने बंगाली कारीगरों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में स्पष्ट किया कि अगर वे बांग्लादेशी हैं और बिना अनुमति के भारत में रह रहे हैं, तो उन्हें भी तुरंत शहर छोड़ देना चाहिए। भार्गव ने कहा कि जो भी लोग इन विदेशी नागरिकों से काम करवा रहे हैं, चाहे वह सराफा बाजार में हों या अन्यत्र, उन्हें भी इसकी जानकारी पुलिस और अन्य एजेंसियों को देनी चाहिए। महापौर ने सभी नागरिकों से अपील की कि इस अभियान में प्रशासन का सहयोग करें और अवैध घुसपैठियों की सूचना तुरंत दें, ताकि शहर की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों के खिलाफ प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

कांग्रेस पर लगाया तुष्टिकरण का आरोप- कांग्रेस पर हमला बोलते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में कांग्रेस और उसके नेताओं ने हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति की है। उन्होंने उमंग सिंगार से सवाल पूछा कि क्या वे बिना अनुमति भारत आए नागरिकों को रहने की अनुमति देंगे? भार्गव ने आरोप लगाया कि मुस्लिम तुष्टिकरण की इसी राजनीति के कारण देश में आतंकवाद बढ़ा है। उन्होंने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है और कांग्रेस की नीति ने इस संकट को और बढ़ावा दिया है। महापौर ने दोहराया कि देश हित में तुष्टिकरण से ऊपर उठकर कठोर निर्णय लिए जाने चाहिए।

विधायक गोलू शुक्ला ने घुसपैठियों को दिया अल्टीमेटम

इंदौर के विधायक गोलू शुक्ला ने अपने क्षेत्र में रह रहे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द विधानसभा क्षेत्र छोड़ दें। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इन्हें ढूंढा जाएगा और कार्रवाई की मांग की जाएगी। शुक्ला ने बताया कि विधानसभा-3 क्षेत्र में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिक बसे हुए हैं, जिन्हें वापस उनके देश भेजने की आवश्यकता है। विधायक ने कहा कि दो दिन के भीतर कार्यकर्ताओं की टीमें सर्चिंग अभियान शुरू करेंगी और जहां भी बांग्लादेशी या पाकिस्तानी नागरिक मिलेंगे, उन्हें इंदौर से बाहर निकाला जाएगा।

संपादकीय

इस 'जबरन' सेल्यूट के मायने

मप्र के पुलिस मुखिया द्वारा राज्य में सभी सांसदों विधायकों को पुलिसकर्मियों द्वारा सेल्यूट ठोकने के फरमान से नया बवाल मच गया है। सवाल उठ रहा है कि क्या जनप्रतिनिधियों को जबर्दस्ती इस तरह सम्मान दिलवाना उचित है? ऐसी मांग किसने की थी, क्या आम नागरिक के साथ पुलिस का सम्मानजनक व्यवहार अपेक्षित नहीं है? और जिन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं, उन्हें सेल्यूट ठोककर पुलिस आम जनता को क्या संदेश देना चाहती है? विपक्षी कांग्रेस ने इस आदेश को मुद्दा बना लिया है। हालांकि कांग्रेस इस मुद्दे पर बंटी नजर आ रही है। पुलिस जनप्रतिनिधियों का सम्मान करे, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। क्योंकि सांसदों, विधायकों को जनता अपने वोट से चुनती है। खुद आम नागरिक भी जनप्रतिनिधियों के आगे नत मस्तक होता है। ऐसे में पुलिस उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करे, यह अपेक्षित ही है। और यह तो पहले भी हो ही रहा था। ऐसे में राज्य के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना को नया आदेश जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या किसी जन प्रतिनिधि ने पुलिस द्वारा उनका सम्मान न करने की शिकायत की थी या फिर पुलिस अपने इस कर्तव्य को भूलने लगी थी? बताया जाता है पिछले कुछ सालों से पुलिसकर्मी केवल मुख्यमंत्री और मंत्रियों को ही सेल्यूट करते थे, जबकि जनप्रतिनिधियों के साथ 'सम्मानजनक' व्यवहार के आदेश थे। इससे जनप्रतिनिधियों का महत्व कम दिखाई देता था। लिहाजा डीजीपी ने 24 अप्रैल को परिपत्र जारी कर राज्य के पुलिसकर्मियों से कहा कि वो सांसदों विधायकों को भी सेल्यूट करें। साथ ही यदि सांसद और विधायक कोई पत्र भेजते हैं, तो उसका उत्तर अपने हस्ताक्षर के साथ समय सीमा में दिया जाए। अगर कोई सांसद, विधायक पुलिस से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे तो पुलिस अफसर प्राथमिकता के आधार पर उनसे मुलाकात करें और गंभीरता से उनकी बात सुनें। यदि कोई सांसद-विधायक मोबाइल या फोन पर जन समस्या को लेकर संपर्क करते हैं तो पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वे उनकी बात को ध्यान से और शिष्टता से सुनें और विधि अनुसार उस पर कार्रवाई करें। इस परिपत्र के संदर्भ में कुछ जनप्रतिनिधियों का कहना है किसी को सम्मान आदेश जारी कर नहीं दिलाया जा सकता। सम्मान का भाव तो भीतर से होना चाहिए। डीजीपी के इस आदेश पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी खफा हैं। उन्होंने पुलिसकर्मियों द्वारा जनप्रतिनिधियों को सेल्यूट मारने के आदेश को 'वर्दी का अपमान' और लोकतंत्र पर हमला बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य में पुलिस की साख रसातल को चली गई है, ऐसे में जनप्रतिनिधियों को सलाम ठोकने का आदेश देने का क्या मतलब है? उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मोहन सरकार वर्दी को सम्मान और संसाधन दे। एक ओर पुलिस अपराधियों से लड़ रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा नेताओं के दबाव से जूझ रही है। और अब यह आदेश उन्हें और भी कमजोर, झुका हुआ और भयभीत बना सकता है। जीतू ने यह सवाल भी किया कि क्या यह निर्णय भाजपा नेताओं की मांग थी? यदि यह आदेश भाजपा नेताओं के दबाव में लिया गया है, तो यह स्पष्ट है कि भाजपा की मंशा पुलिस को स्वतंत्र नहीं, सत्ता का सेवक बनाना है। जीतू पटवारी ने एक तार्किक बात यह कही कि प्रदेश में भाजपा के 29 सांसदों में से 9 पर यानी कि 31 फीसदी जनप्रतिनिधियों पर विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज हैं। ऐसे क्या पुलिस अपराधियों को भी सेल्यूट करेगी? हालांकि जीतू के इस बयान को विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पर परोक्ष वार के रूप में भी देखा जा रहा है। उमंग पर कुछ फौजदारी मामले चल रहे हैं। उमंग ने जीतू की मांग को गैर जरूरी बताया है।

दवा 'बैन' भी एक प्रकार की व्यापारिक रणनीति

नजरिया

नृपेन्द्र अभिषेक नृप

लेखक स्तंभकार हैं।

दवाएं विज्ञान की एक ऐसी सौगात हैं, जिन्होंने अनगिनत जिंदगियों को बचाया है और मानवता को गंभीर बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत दी है। किंतु जब यही दवाएं मुनाफे की अंधी दौड़ में जहरीले हथियार बन जाएं, तो वह विज्ञान नहीं बल्कि व्यापार बन जाती हैं। एक ऐसा व्यापार, जिसमें लोगों की जान जोखिम में डालने की कीमत पर कुछ मुट्ठी भर कंपनियां अरबों का मुनाफा कमाती हैं। भारत में हाल ही में इस दिशा में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप सामने आया है, जब केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने पैंतीस 'फिक्स-डोज़ कॉम्बिनेशन' यानी एफडीसी दवाओं पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। यह निर्णय न केवल एक साहसिक कदम है, बल्कि आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक नज़ीर भी।

इन प्रतिबंधित दवाओं में से कई वर्षों से बुखार, दर्द, एलर्जी और सर्दी जैसी सामान्य बीमारियों के इलाज में प्रयुक्त हो रही थीं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि जो दवाएं इतने वर्षों से खुले बाजार में बिक रही थीं, उनके उपयोग से पहले क्या कोई वैज्ञानिक मूल्यांकन नहीं हुआ था? अगर हुआ था, तो आखिर उन दवाओं को अब खतरनाक क्यों माना जा रहा है? और यदि मूल्यांकन ही नहीं हुआ था, तो फिर वे दवाएं इस लंबे समय तक बाजार में कैसे उपलब्ध रहीं? इन सवालों के उत्तर हमें भारत में दवा नियमन की जटिलता, नियामक संस्थाओं की कार्यक्षमता, दवा कंपनियों के प्रभाव और नीति निर्धारण की कमजोरियों की ओर ले जाते हैं।

फिक्स-डोज़ कॉम्बिनेशन यानी एफडीसी दवाएं दो या दो से अधिक सक्रिय औषधीय घटकों का मिश्रण होती हैं, जो एक ही गोली या सिरप के रूप में दी जाती हैं। इनका उद्देश्य कभी-कभी सुविधाजनक उपचार होता है, जैसे मधुमेह, टीबी या एड्स जैसी बीमारियों के लिए जिनमें एक साथ कई दवाएं देनी होती हैं। परंतु कई बार दवा कंपनियां एफडीसी का सहारा मुनाफाखोरी के लिए लेती हैं- वे बिना वैज्ञानिक प्रमाण या चिकित्सा आवश्यकता के विभिन्न घटकों को जोड़कर नई दवाएं बना देती हैं, जिन्हें बाजार में उतारने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार का सहारा लिया जाता है।

इनमें से अनेक एफडीसी दवाएं कोई अतिरिक्त चिकित्सीय लाभ नहीं देतीं, बल्कि कई बार इनसे दुष्प्रभाव और जटिलताएं बढ़ जाती हैं। उदाहरण के लिए, ऐसी दवाएं जिनमें दर्द निवारक के साथ एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड मिला होता है, वे बिना किसी चिकित्सकीय औचित्य के रोगियों को दिए जाते हैं। नतीजा यह होता है कि न केवल मरीज की सेहत बिगड़ती है, बल्कि दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता (Antimicrobial Resistance) भी बढ़ती है, जो आज वैश्विक स्वास्थ्य संकट बन चुका है।

भारत में एफडीसी दवाओं के उत्पादन और बिक्री का इतिहास भी काफी उलझा हुआ है। दरअसल, दवा नियमन की प्रणाली केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है। जहां नई दवाओं को केंद्रीय संस्था सीडीएससीओ से अनुमोदन लेना होता है, वहीं उत्पादन और वितरण की अनुमति राज्यों के औषधि नियंत्रकों द्वारा दी जाती है। कई बार दवा कंपनियां इसी भ्रमित व्यवस्था का लाभ उठाकर बिना केंद्रीय स्वीकृति के भी राज्यों से अनुमति प्राप्त कर लेती हैं और वर्षों तक अपनी दवाएं बेचती रहती हैं। यह दोहरी प्रणाली ऐसी स्थिति पैदा करती है, जिसमें दवाएं कानूनन बाजार में रहती हैं, भले ही वे वैज्ञानिक दृष्टि से सुरक्षित न हों।

डॉ. ज्योति सिंह का मानना है कि जिन लोगों ने पहले से इन प्रतिबंधित दवाओं का सेवन किया है, उनकी शारीरिक प्रतिरोधक प्रणाली पर इसका गहरा असर पड़ा है। अब सामान्य दवाएं उन पर प्रभावी नहीं रह गई हैं, जो भविष्य के लिए एक गंभीर खतरे का संकेत है। उनका कहना है कि इन दवाओं पर लगाया गया प्रतिबंध वस्तुतः कोई ठोस लाभ नहीं पहुंचा रहा है। वह इस बात पर ज़ोर देती हैं कि आजकल 'बैन' भी एक प्रकार की व्यापारिक रणनीति बन चुका है। यह

एक ऐसी चतुर चाल है जिससे सरकार और दवा कंपनियाँ अधिक मुनाफा कमा सकें। पहले एक ही दवा में तीन-चार सक्रिय तत्व एक साथ मिला दिए जाते थे, जिससे एक ही गोली पर्याप्त होती थी। अब उस एक दवा के स्थान पर मरीज को तीन अलग-अलग गोलियाँ लेनी पड़ रही हैं, जिनमें वही तत्व अलग-अलग रूप में दिए जा रहे हैं। इससे न केवल रोगी की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ता है, बल्कि दवा कंपनियों को भी ज़्यादा लाभ मिलता है।

डॉ. सिंह यह भी इंगित करती हैं कि पेट की गैस से संबंधित प्रसिद्ध दवा 'रैनिटिडीन', जिसमें पाए जाने वाले एक रसायन को कैंसरजनक माना गया है, आज भी भारत में धड़ल्ले से बिक रही है, जबकि कई विकसित देशों में इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा चुका है। यह दर्शाता है कि दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय कहीं न कहीं राजनीतिक, व्यापारिक और रणनीतिक हितों से भी संचालित होता है। हर देश अपनी प्राथमिकताओं, जरूरतों और दबावों के अनुरूप इस विषय में अलग-अलग रवैया अपनाता है।

2016 में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति (डॉ. चंद्रकांत कोकाटे समिति) ने लगभग 6,000 एफडीसी दवाओं की जांच की थी और पाया था कि इनमें से कई को न तो किसी चिकित्सकीय आधार पर अनुमोदित किया गया था और न ही उनका पर्याप्त मूल्यांकन किया गया था। समिति ने सैकड़ों एफडीसी पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। इसके बाद कुछ दवाएं प्रतिबंधित की गईं, लेकिन दवा कंपनियों ने कानूनी लड़ाई लड़ते हुए कई फैसलों पर रोक लगवा दी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय सीडीएससीओ के वैज्ञानिक मूल्यांकन पर छोड़ दिया कि किन दवाओं को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

हालिया आदेश उसी प्रक्रिया का परिणाम है। लेकिन यह भी स्पष्ट करता है कि जब तक वैज्ञानिक मूल्यांकन और नियामक कार्रवाई के बीच लंबा समय रहेगा, तब तक असुरक्षित दवाएं आमजन तक पहुंचती रहेंगी। ऐसे में यदि किसी दवा को पंद्रह-बीस वर्षों तक उपयोग के बाद प्रतिबंधित किया जाता है, तो सवाल यह उठता है कि उस समयावधि में जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या दवा कंपनियों की कोई जवाबदेही तय की जाएगी? क्या सरकार ऐसे मामलों में जनहित याचिकाओं के माध्यम से मरीजों को मुआवज़ा दिलाने के लिए आगे आएगी?

यह भी जरूरी है कि दवाओं के उत्पादन, मूल्य निर्धारण, प्रचार और वितरण से संबंधित पारदर्शी तंत्र स्थापित हो। आज दवा कंपनियां चिकित्सा प्रतिनिधियों के माध्यम से डॉक्टरों को अपने उत्पादों के लिए प्रभावित करती हैं। मरीज डॉक्टर पर भरोसा करके वह दवा लेता है, लेकिन अक्सर उसे यह पता नहीं होता कि उस दवा की जरूरत थी या नहीं। यदि डॉक्टर खुद उस दवा की प्रभावशीलता से अनभिज्ञ है, तो मरीज अंधेरे में तीर चलाता है। इसी कारण कई बार ऐसी दवाएं भी धड़ल्ले से बिकती हैं जो या तो बेअसर होती हैं या खतरनाक।

वर्तमान में स्वास्थ्य सेवाओं का व्यवसायीकरण भी इस संकट को गहरा करता है। मुनाफे के चक्कर में न केवल दवा कंपनियां, बल्कि फार्मेसी, अस्पताल और डॉक्टरों की भूमिका भी संदेह के घेरे में आती है। भारत जैसे देश में जहां बड़ी आबादी अशिक्षित और गरीब है, वहां चिकित्सा सेवा का एकमात्र उद्देश्य जनस्वास्थ्य होना चाहिए, न कि मुनाफा कमाना। लेकिन जब सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता घटती है और लोगों को निजी क्षेत्र की शरण में जाना पड़ता है, तब दवा कंपनियों को मुनाफा कमाने का बड़ा अवसर मिलता है। दुर्भाग्यवश, इस अवसर का उपयोग लोगों की सेहत की कीमत पर किया जाता है।

इस पूरी स्थिति में एक अन्य गंभीर पक्ष है जनजागरूकता की कमी। आज भी बहुत से लोग बिना डॉक्टर की सलाह के दवाएं लेते हैं। वे मेडिकल स्टोर से OTC (Over-the-Counter) दवाएं मांगते हैं, जो आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। कई बार दुकानदार भी किसी रोग के लिए बिना जानकारी के दवाएं सुझा देते हैं। यह प्रथा न केवल दवा के गलत प्रयोग को बढ़ावा देती है, बल्कि गंभीर दुष्प्रभावों की आशंका को भी जन्म देती है। इस पर अंकुश लगाने के लिए न केवल कड़े कानूनों की आवश्यकता है, बल्कि जनजागरूकता अभियान भी जरूरी हैं।

दूसरी ओर, दवा कंपनियों का यह तर्क भी विचारणीय है कि किसी दवा को प्रतिबंधित करने से पहले उसका पूर्ण वैज्ञानिक मूल्यांकन होना चाहिए। कई बार नियामक संस्थाएं केवल सतही परीक्षणों के आधार पर निष्कर्ष निकालती हैं, जिससे फार्मा उद्योग में अनिश्चितता और असमंजस का माहौल बनता है। इससे नवाचार और अनुसंधान को भी झटका लगता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि दवा प्रतिबंधों की प्रक्रिया पारदर्शी, वैज्ञानिक और न्यायसंगत हो। कोई भी निर्णय राजनीतिक दबाव या जनभावनाओं के तहत नहीं, बल्कि ठोस साक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए।

हालांकि यह भी सच है कि भारत विश्व में दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यहां बनी जेनेरिक दवाएं दुनियाभर में सस्ती और सुलभ मानी जाती हैं। परंतु यदि इस उपलब्धि के पीछे छिपी गुणवत्ता और सुरक्षा की अनदेखी की जाती रही, तो यह 'फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड' की पहचान भी खतरे में पड़ सकती है। अतः आवश्यक है कि भारत अपनी नियामक प्रणाली को और अधिक सक्षम बनाए, जिसमें न केवल उत्पादन की अनुमति देने से पहले, बल्कि उसके बाद भी निरंतर निगरानी हो।

इन तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए यह स्पष्ट होता है कि खतरनाक दवाओं पर रोक लगाने का कार्य केवल एक सरकारी आदेश नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य नीति, नैतिकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और जनहित की रक्षा का समवेत प्रयास होना चाहिए। जब तक दवा कंपनियों की जवाबदेही तय नहीं होगी, डॉक्टरों की भूमिका पारदर्शी नहीं बनेगी, और सरकार अपनी जिम्मेदारी को लेकर संवेदनशील नहीं होगी, तब तक कोई भी नियम केवल कागजों में ही सीमित रहेगा।

यह केवल दवाओं का मसला नहीं, बल्कि इस देश के करोड़ों नागरिकों के जीवन और विश्वास का प्रश्न है। स्वास्थ्य कोई व्यापार नहीं, बल्कि मानवाधिकार है। यदि मुनाफा जनस्वास्थ्य से ऊपर बैठा दिया गया, तो वह समाज न विज्ञान को संभाल पाएगा, न ही सभ्यता को।

अब पाक का सही, पक्का और स्थाई इलाज जरूरी

विदेश नीति

चेतनादित्य आलोक

लेखक स्तंभकार हैं।

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम के लोकप्रिय टूरिस्ट साइट बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने जिस प्रकारसे धर्म पूछकर निहत्थे, निर्दोष और मासूम पर्यटकों पर गोलियों की बौंछार करके 28 हिंदुओं समेत 30 लाशें बिछा दीं, वह उनकी राक्षसी प्रवृति का परिचायक है। पहलगाम की घाटी बैसरन में बेहद क्रूरतापूर्ण, दुष्टतापूर्ण, अमानवीय एवं असहनीय घटना को अंजाम देने वाले अत्यंत निर्मम, वीभत्स और दैत्य प्रकृति आतंकवादियों को सभ्य मानव समाज के बीच रहने का कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यही नहीं, उन्हें मानव बस्तियों और समाज से दूर घने और अंधकारपूर्ण जंगलों में भी नहीं रहने दिया जा सकता, क्योंकि यदि उन्हें वहां रहने दिया गया तो जंगली जानवरों और यहां तक कि स्वयं जंगलों का भी महाविनाश निश्चित ही हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में यह प्रश्न किया जाएगा कि फिर वे कहां पर रहें... जाहिर है कि इस प्रश्न का केवल एक ही उत्तर हो सकता है, और वह है कि उनकी अधोगति को उर्ध्वगति में परिवर्तित कर उनका कल्याण कर दिया जाए। यानी उन्हें भी ऊपर भेज दिया जाए, लेकिन यह मामला इतना सहज भी नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा किया गया तो मानव अधिकारों की बात करने वाले लोग और संगठन उन 'राक्षसों के भी मानव अकिारों' की वकालत करना शुरू कर देंगे।इतना ही नहीं, येउन 'राक्षसों के मानव अकिारों' की वकालत बेहद जोर-शोर से करेंगे।

ऐसा ये इसलिए करेंगे, ताकि उनकी आवाज दूर-दूर तक पहुंच सके, अन्यथा भारत के कोने-कोने तथा दूर देशों में बैठे इनकेपैरोकारों, सहयोगियों और हमदर्दों से इन्हें पान-फूल और शाबाशियां कैसे मिल पाएंगी। वैसे, देखा जाए तो हम सब इनके कृत्यों के लिए इन्हें व्यर्थ ही बदनाम करते रहते हैं। वास्तव में,इसमें इनका कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की वकालत करना तो हमेशा से ही, बल्कि कहा जाए कि इनका खानदानी व्यवसाय रहा है। ...और यही कारण है कि यह व्यवसाय इनसे छुड़ाए नहीं छूटताहै। जाहिर है कि पुश्तों से 'मुंह की लगी' इतनी आसानी से कैसे छूटेगी भला। खैर, नहीं छूटती तो, न छोड़ें ये, हम इनके इस 'मुंह की लगी' को छुड़ाने का जिम्मा ले लें, यही उचित है। तात्पर्य यह कि ये अपना कार्य (अपनी वकालत) करते रहें... आतंकवादी भी (अपनी राक्षसी प्रवृति को आगे बढ़ाने का) अपना नियत कार्य करते रहें... औरहमसभी 142 करोड़ भारतवासी एकजुट होकर अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से अंजाम तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहें, ताकि इनकी 'मुंह की लगी' वकालत को भी सही राह दिखाई जाए और उनकी राक्षसी प्रवृति का समूल नाश भी किया जा सके। स्मरण रहे कि जब तक इनकी 'मुंह की लगी' और उनकी राक्षसी प्रवृतिका पूरा-पूरा हिसाब नहीं किया जाएगा, वे हमारे निहत्थे, निर्दोष और मासूम लोगों के साथ धर्म पूछ-पूछकर खून की होली यों ही खेलते रहेंगे।

जम्मू-कश्मीर में हुए हिन्दुओं के कुछ अन्य बड़े नरसंहारों में 13-14 अगस्त 1993 को डोडा जिले के किश्तवाड़ कस्बे में सरथल-किश्तवाड़ मार्ग पर यात्री बस से उतार कर 17 हिन्दू यात्रियों को मारना,14 मई 1995 को दोहरी भरथ में 06 हिन्दुओं की हत्या करना, 15 जनवरी 1996 को डोडा जिले के किश्तवाड़ कस्बे के बरशाला क्षेत्र में 16 हिन्दुओं की हत्या करना, 12 जनवरी 1996 को डोडा जिले के भद्रवाह कस्बे में 07 हिन्दुओं की हत्या करना,06 मई 1996 को डोडा की रामबन तहसील के सुम्बर गांव में 17 हिन्दुओं की हत्या करना,07-08 जून 1996 को डोडा जिले के कमलाड़ी गांव में 09 हिन्दुओं की हत्या करना, 25 जून 1996 को डोडा के सियुधार क्षेत्र में 13 हिंदुओं की हत्या करना,07 अप्रैल 1997 को कश्मीर घाटी के संग्रामपुरा गांव में 07 कश्मीरी पंडितों की हत्या करना, 24 सितम्बर 1997 को राजौरी जिले के सवाड़ी गांव में 08 हिन्दुओं की हत्या करना, 26 जनवरी 1998 को कश्मीर के वंदहामा गांव में 23 कश्मीरी पंडितों की हत्या करना, 16 अप्रैल 1998 को डोडा के देस्सा क्षेत्र में 09 की हत्याकरना, 17 अप्रैल 1998 को उधमपुर के प्राणकोट एवं ढाकीकोट गांवों में 29 लोगों की हत्या करना,05 मई 199 को पुंछ के सुरनकोट क्षेत्र में 05हिन्दुओं की हत्या करना और06 मई 1998 को डोडा के देस्सा गांव में 11 सुरक्षा समिति के हिन्दू सदस्यों की हत्या करना शामिल है।

इनके अतिरिक्त, 19 जून 1998 को डोडा के चम्पनारी में 29 हिन्दू बारातियों की हत्या करना,जिनमें 03 दूल्हे भी शामिल थे। 27 जुलाई 1998 को डोडा में किश्तवाड़ के छिन्नाठकुराई एवं श्रवण गांवों में 20 हिन्दुओं की हत्या करना, 28 जुलाई 1998 को डोडा के सरवान क्षेत्र में 08 लोगों की हत्या करना,19 फरवरी 1999 को राजौरी जिले के बल-चराल गांव में 09 हिन्दू बारातियों की हत्या करना,19 फरवरी 1999 को राजौरी में कालाकोट क्षेत्र के बनियारी में 10 हिन्दुओं की हत्या करना, 29 जून 1999 को अनंतनाग के संथू गांव में 12 बिहारी श्रमिकों की हत्या करना, 01 जुलाई 1999 को मेंढर के आड़ी गांव में दो हिन्दू परिवारों के 09 सदस्यों की हत्या करना, 19 जुलाई 1999 को डोडा के काठरी गांव में 05 हिन्दू परिवारों के 15 सदस्यों की हत्या करना, 28 फरवरी 2000 को पुंछ के मेंढर कस्बे में 05 हिन्दुओं की हत्या करना, 29 फरवरी 2000 को काजीगुंड में 05 सिख ट्रक चालकों की हत्या करना, 20 मार्च 2000 को कश्मीर के छत्तीसिंह पोरा में 36 सिखों की हत्या करना,01 अगस्त 2000 को पहलगाम में 32 हिंदुओं की हत्या करना,जिनमें 29 अमरनाथ यात्री भी शामिल थे,02 अगस्त 2000 को डोडा के बनिहाल कस्बे केपोगल में 12 हिन्दुओं की हत्या करना तथा 02 अगस्त सन् 2000 को अनंतनाग के अच्छावल में आठ प्रवासी श्रमिकों की हत्या करना शामिल है।

इसी प्रकार, 02 अगस्त 2000 को अनंतनाग के काजीगुंड में 19 प्रवासी श्रमिकों की हत्या किया जाना, 22 नवम्बर 2000 को बनिहाल में राजमार्ग पर 05 हिन्दू-सिख ट्रक ड्राइवरों की हत्या करना, 24 नवम्बर 2000 को डोडा के किश्तवाड़ कस्बे में 05 हिन्दुओं की हत्या किया जाना,03 फरवरी 2001 को श्रीनगर के महजूर नगर में 08 सिखों की हत्या करना,10 मई 2001 को किश्तवाड़ के अठोली-पाडर के सजार कस्बे में 08 हिन्दुओं की गला रेत कर हत्या करना, 21 जुलाई 2001 को अमरनाथ यात्रा के पड़ावस्थल शेषनाग में 07 तीर्थयात्रियों सहित 13 की हत्या किया जाना,21 जुलाई 2001 को डोडा जिले के किश्तवाड़ तहसील के छात्रू क्षेत्र में 05 हिन्दुओं की हत्या करना, 21 जुलाई 2001 को डोडा जिले की किश्तवाड़ तहसील के वाडवान क्षेत्र में चिरजी मोहड़ा गांव में 15 हिन्दुओं की हत्या किया जाना,04 अगस्त 2001 को डोडा जिले के किश्तवाड़ तहसील के सरूतधार क्षेत्र में 16 हिन्दुओं की हत्या करना,01 जनवरी 2002 को पुंछ के मगवार गांव में एक हिन्दू परिवार के 06 सदस्यों की हत्या करना, 31 जनवरी 2002 को उधमपुर के रियासी कस्बे में 04 प्रवासी श्रमिकों की हत्या किया जाना, 17 फरवरी 2002 को राजौरी के कालाकोट क्षेत्र के निराला गांव में एक हिन्दू परिवार के 08 सदस्यों की हत्या करना एवं 30 मार्च 2002 को जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर हमला कर 08 हिन्दुओं को मौत के घाट उतार दिया जाना शामिल है।

ऐसे ही, 08 अप्रैल 2002 को उधमपुर के अरनास गांव में सात हिन्दुओं की सामूहिक हत्या करना, 14 मई 2002 को जम्मू के कालूचक में किए गए भीषण नरसंहार में 34 हिन्दुओं की हत्या करना, 15 जून 2002 को डोडा के किश्तवाड़ क्षेत्र में एक धार्मिक यात्रा पर हमला कर 05 हिन्दुओं की हत्या करना, 16 जून 2002 को उधमपुर के बडर गांव में एक ही हिन्दू परिवार के 05 सदस्यों की हत्या किया जाना, 18 जुलाई 2002 को जम्मू के कासिम नगर में 29 लोगों की हत्या करना, जिनमें मरने वाले सभी प्रवासी श्रमिक थे,06 अगस्त 2002 को नुनवान-पहलगाममें 10 अमरनाथ श्रद्धालुओं का नरसंहार करना,23 नवम्बर 2002 को रघुनाथ मंदिर पर हुए दूसरा आत्मघाती हमलाकर 14 हिंदुओं की हत्या किया जाना, जिनमें 11 नागरिक, 01 सुरक्षाकर्मी एव 02 आतंकवादी शामिल थे,एक अन्य आतंकी हमले में जम्मू में 15 पुलिसकर्मियों और 02 नागरिकों की हत्या करना, 23 मार्च 2003 को कश्मीर के पुलवामा जिले में शोपियां के पास नाड़ीमर्ग गांव में आतंकवादियों द्वारा 24 कश्मीरी पंडितों की हत्या करना तथा 30 अप्रैल 2006 को उधमपुर के बसंतगढ़ में 07 हिन्दुओं और डोडा के कुलहान इलाके में 22 हिन्दुओं की हत्याकिया जाना शामिल है। दरअसल, उन आतंकवादियों की फितरत ही यही है। वे हमेशा से पाकिस्तानी सेना द्वारा प्रायोजित धार्मिक (इस्लामिक) जिहाद के अंतर्गत ऐसे ही योजनाएं बनाकर हिंदुओं की हत्याएं करते आए हैं।

गौरतलब है कि हाल ही में, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों, संत्रियों, आर्मी अफसरों, फौजियों आदि की मौजूदगी में हिंदुओं के विरूद्ध जहरीली तकरीर दी थी। उसने हिंदुओं को मुसलिमों से बदतर बताया तथा धार्मिक (इस्लामिक) जिहाद के लिए पाकिस्तानी फौज एवं आतंकवादियों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया था, जिसके महज कुछ ही दिनों के भीतर उसके पाले-पोसे कुत्तों ने पहलगाम के लोकप्रिय टूरिस्ट साइट बैसरन घाटी में 28 हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया। इससे पहले, 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर हुआ पुलवामा अटैक भी इसी जेनरल मुनीर ने कराया था, जबकि हम उनके आतंकियों को मारकर अपनी पीठ थपथपाते रहे। पता नहीं हम इस बात को क्यों नहीं समझ पाते हैं कि हिंदुओं की हत्याओं का ये सिलसिला तब तक नहीं रूकने वाला, जब तक कि पाकिस्तान का सही, पक्का और स्थाई ईलाज नहीं किया जाएगा। इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि हम समस्या की जड़, यानीभारत और 142 करोड़ भारतीयों के वास्तविक दुश्मन को पहचानें। वह दुश्मन पाकिस्तानी आर्मी चीफजेनरल मुनीर है, मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकी नहीं। ये आतंकी तो महज उसके प्यादे हैं, जिनका उपयोग कर पाकिस्तान बार-बार भारत की आत्मा को लहूलुहान करता रहता है। जाहिर है कि हमें भी अब अपना एजेंडा बदलना होगा। हमें पाकिस्तानी पंजाबी फौजियों का खून बहाना होगा, ताकि उन्हें उस जगह पर चोट लगे, जहां उन्हें सबसे अधिक दर्द होता है। यकीन मानिए, यदि हमने ऐसा कर दिया तो उनका सही, पक्का और स्थाई ईलाज हो जाएगा। इसलिए बिना देर किए भारत सरकार और एजेंसियों को पाकिस्तान का सही, पक्का और स्थाई ईलाज करने में जुट जाना चाहिए।

माननीय का साहब का सैल्यूट

कटाक्ष

डॉ. हरीशकुमार सिंह

लेखक व्यंग्यकार हैं।

मध्यप्रदेश के पुलिस मुखिया ने नया फरमान जारी किया है कि पुलिस अधिकारियों को वर्दी में ड्यूटी पर होने के दौरान सांसदों और विधायकों को सैल्यूट ठोकना होगा। सरकार के इस फरमान से ईमानदार पुलिसकर्मी हैरान परेशान हैं कि सम्मान पूर्ण व्यवहार तो ठीक है मगर यह सैल्यूट क्यों? कैसे-कैसे महानुभाव भी आजकल जनप्रतिनिधि बन जाते हैं यह हम सब जानते हैं। आजकल राजनीतिक दल अधिकतर जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट देते हैं और फिर यह नहीं देखते कि जिसे टिकट दिया गया है उसका और पुलिस का तो चोली दामन का साथ रहा है। जनप्रतिनिधि बनने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता जरूरी नहीं है जबकि पुलिस के अधिकारी तो पढ़-लिखकर,परीक्षा उत्तीर्ण कर बड़ी मुश्किल से अधिकारी बन पाते हैं। सैल्यूट का भी प्रोटोकॉल होता है कि पुलिस में छोटा अधिकारी अपने बड़े अधिकारी को सैल्यूट करता है। जो जनप्रतिनिधि खुद चुनाव के समय, जनता को सैल्यूट कर, जनता के दिए गए वोट से चुनकर आये वो जनता से ही बड़े नहीं होते तो पुलिस वालों से बड़े कैसे हो सकते हैं। जनप्रतिनिधि कोई साहब का पद नहीं है बल्कि उस क्षेत्र की जनता ने आपको अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजा है कि आप ,जनता की परेशानियों, वाजिब मांगों और क्षेत्र के विकास के लिए राजधानी में अपनी आवाज बुलंद करें और अपने जनप्रतिनिधि होने को सार्थक करें, न कि आप अपने आपको पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से ऊपर समझें।

जब आप युवा नेता थे तब जन आंदोलन के समय, कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए इन्हीं पुलिस वालों ने आप पर लट्ठ बरसाए होंगे और अब चुनाव जीतकर जनप्रतिनिधि बन जाने पर, क्या आप पुलिसकर्मियों से सैल्यूट करवा कर बदला लेना चाह रहे हैं। जब आप राजनीति के दम पर बिना रजिस्ट्रेशन की बसें चलाकर आरटीओ को सेट कर कंडम बस में सवारियों को ढोकर, कमाने में लगे थे और कभी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने पर कई जानें चली गईं थीं तब इसी पुलिस ने आपकी कॉलर पकड़कर थाने में लाया होगा और फिर एक दिन टिकट पाकर जीतकर जनप्रतिनिधि बन जाने से क्या आप पुलिस के माईबाप बन गए जो पुलिस आपको सैल्यूट करेगी। जिंदगी भर आपने नकली दारू बेचकर कमाई की और पुलिस ने कई बार आपका सार्वजनिक अभिनंदन भी किया होगा और रुपये देकर,टिकट लाओ योजना में एक दिन आप टिकट ले आये और रातों रात दारू - रुपये बांटकर,चुनाव में जीत गए और अब आप चाहते हो कि वही पुलिस आपको सैल्यूट करे। जब आपकी पार्टी सत्ता में रही तो कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी की बदौलत अवैध खनन कर रेती, गिट्टी ,मिट्टी निकाल निकाल कर धरती की छाती फाड़कर आपने अपनी हवेली बना डाली और जब टिकट मिल गया और जीत गए तो अब आप चाहते हो कि वही पुलिस जो मौका आने पर आपके डंपर जब्त करती रही अब आपको सैल्यूट करे। सार यह है कि जो पुलिस अभी तक आपको कभी कभार जिला बदर भी करती रही आप चाहते हो कि अब प्रायश्चित कर आपको सैल्यूट करे। न सारे पुलिस वाले बेईमान हैं और न ही सारे जनप्रतिनिधि अपराधी हैं। बेईमान पुलिस बेईमान जनप्रतिनिधि को खुद ही सैल्यूट करती है क्योंकि दोनों सहोदर हैं। ईमानदार पुलिस और ईमानदार जनप्रतिनिधि भी एक दूसरे की इज्जत करते हैं। इसलिए इसके बजाय यदि आपने जनप्रतिनिधि के नाते यह मांग की होती कि यह मेरे क्षेत्र की जनता है,यह जब कोई शिकायत लेकर आए तो तुरंत इसकी रपट लिख लेना और मुझे मान सम्मान दो या न दो पर जनता को थाने में इज्जत देना,कुर्सी देना और समाधान देना तो आपकी इज्जत इतनी बढ़ जाती कि आपके क्षेत्र की जनता आपको देखते ही स्वयं नतमस्तक हो जाती और आपको पुलिस के सैल्यूट की जरूरत ही नहीं पड़ती।

सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पी.जी. इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेस प्रा. लि., राउखेड़ी, देवास रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 662, साईं कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक - उमेश त्रिवेदी
संपादक (म.प्र.) -विनोद तिवारी
कार्यकारी प्रधान संपादक - अजय बोकिल
स्थानीय संपादक - हेमंत पाल
प्रबंध संपादक - अरुण पटेल

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

कश्मीर वादी में आतंकवादी

व्यंग्य

सूर्यदीप कुशवाहा

तड़-तड़ गोलियां चली हैं जी। खून से सनी लाशें पड़ी हैं। खबरें देखें इन्हीं से पटी हैं। अब सोशल मीडिया में मजहबी गालियां बरस रही हैं। यहां कोई किसी से पीछे नहीं है। यहां सब दुःख जता रहे हैं और कुछ एसी में बैठे रसमलाई खा रहे हैं। पड़ोस में किसी के मरने पर भी न जाने वाले भी आभासी वाल पर गम में मरे जा रहे हैं कि सुनकर कलेजा बेदम हो जा रहा है। लेकिन अनर्गल बयानबाजी से उनको दम मिल रहा है। बताओ क्या करें हम? उनको समझाओ भाई हम सरकार नहीं हैं कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूत कर दें। हम भारत के आम आदमी हैं। हम आतंकी घटना की संवेदना के साथ भर्त्सना कर सकते हैं और लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। आतंकवाद का शर्तिया इलाज होना जरूरी है। इसमें कोई भी नहीं मजबूरी है। देश की एकता अखंडता सोशल मीडिया में खंड -खंड करने की चेष्टा है। जो धर्म पूछी जाति नहीं में अटके हैं , वही बेचारे भूलें-भटके हैं। जाति तो हमारे देश का नासूर है। इस नासूर को फोड़ना किसका काम है।भारत की खूबसूरती ही विविधता में एकता है। हालांकि आभासी दुनिया में सर जी/मैडम जी जैसा ज्ञानी व्यक्ति मुफ्त सलाह बांट रहा है। इस हरकत से देश बटेगा नहीं। आतंकी भेड़िये भी हिंदू-मुस्लिम करके चले गए। इससे उनके खतरनाक मंसूबो के तो भाग खुल गए। सब अपनी पोस्ट पे पोस्ट आग लगाने में लग गए। लेकिन अमन चैन छीन लिया आतंकी ने और भारतीय बेचैन हैं। क्या मुझे आपको भी भारतीय बनना है या बस हिंदू/मुस्लिम। देश की एकता अखंडता के लिए तय आपको करना है।बताओ क्या सही करें। आप जब वहां होते तो बस घोड़े, गाड़ी और होटल वालों की अच्छाई अपनी आँखों से देख पाते। अंधभक्तों का बदबूदार बयान सोशल मीडिया में गंधाता रहता है। विपक्ष तो सही बोलने को भी तरसता रहता है। सुगंध और दुर्गन्ध के पाटन के बीच में पिसाता सीधा आदमी है। मजहबी कीड़ा बनोगे तो दिमाग कुंद होगा और आँखों पर धुंध होगा। देश के प्रति जिम्मेदारी भी कोई चीज है। हर चीज में नफरत ढूढ़ते नाचीज़। जब-जब आतंक चलेगा अपनी चाल तो क्रूर, निरंकुश बनेगा विकराल। आतंकवाद के फन का मर्दन तब उचित है और आतंकवाद का अंत तो सुनिश्चित है। होंगी नापाक जब भी पाक की हरकतें, छिप-छिप के छीनना चाहेगा हमारी बरकतें तो सर्जिकल का विकल्प उचित है। नफरत करने वाले किसी के नहीं हो सकते हैं और पाक के नापाक मंसूबे हैं, इसलिए कश्मीर वादी में आतंकवादी..!

योग साधना

कर्मयोगी

(पत्रकार और योग विशेषज्ञ)

योगासनों के 12 विश्व रिकॉर्ड बनाने का संकल्प

इस साल का विश्व योग दिवस 21 जून को है। होने वाले इस आयोजन में देश-विदेश के हजारों योग साधक हिमालय सिद्ध अक्षर के मार्गदर्शन में पसीना बहा रहे हैं। इस साल की प्रतियोगिता में जो आसन शामिल हैं उनमें भद्रासन, अधोमुख श्वानासन, शलभासन, गरुड़ासन, एक पाद पादागुंनुष्ठासन, उभय पादागुंनुष्ठासन,एक पाद राजकपोतासन शामिल हैं। वहीं जो पिछले रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी है, उनमें सेतुबंध सर्वांगासन, सर्वांगासन, वीरभद्रासन व उत्कटासन शामिल हैं।

बें गलुरु स्थित अक्षर योग केंद्र इन देश-विदेश के हजारों योग साधकों की गहमा-गहमा का केंद्र बना हुआ है। विश्वविख्यात योग गुरु हिमालय सिद्ध अक्षर के नेतृत्व में इतिहास रचने की तैयारी है। जिसमें अमेरिका, यूरोप,अफ्रीका व एशिया के हजारों प्रतिभागी 12 गिनीज बुक रिकॉर्ड के ऑफिशियल प्रयास की तैयारी में जुटे हैं। यह आयोजन इस बार विश्व योग दिवस पर होने जा रहा है। हिमालय सिद्ध अक्षर कहते हैं कि यह प्रयास हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण के साथ दुनिया को यह बताना है कि इसके असली वारिस हम हैं। उल्लेखनीय है कि इस बार 11वें विश्व योग दिवस के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थीम 'योग फॉर वन अर्थ, वन हेल्थ' घोषित की है।

साल 2010 में स्थापित अक्षर योग केंद्र यह आयोजन पहले ताइवान में करने जा रहा था। लेकिन भू-राजनीतिक कारणों की चुनौती के चलते इस आयोजन को बंगलूरू में ही आयोजित करने का फैसला किया है। अक्षर योग केंद्र के नाम पहले ही योगासनों के नौ विश्व रिकॉर्ड दर्ज हैं। जिसमें संस्थान के नाम वर्ष 2021 में वशिष्ठासन, 2022 में धनुरासन, वर्ष 2023 में उष्ट्रासन, हलासन तथा 2024 में चक्रासन, नौकासन, कौडिन्यासन, नटराजनासन व सूर्य नमस्कार के लिये गिनीज बुक रिकॉर्ड दर्ज हो चुके हैं। इस बार इस ऑफिशियल प्रयास के लिए गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्था की सौ सदस्यों की टीम के साथ संस्था के बड़े अधिकारी बंगलूरु में आसनों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे। इस साल के विश्व योग दिवस 21 जून को होने वाले इस आयोजन में देश-विदेश के हजारों योग साधक हिमालय सिद्ध अक्षर के मार्गदर्शन में पसीना बहा रहे हैं। इस साल की प्रतियोगिता में जो आसन शामिल हैं उनमें भद्रासन, अधोमुख श्वानासन, शलभासन, गरुड़ासन, एक पाद पादागुंनुष्ठासन, उभय पादागुंनुष्ठासन,एक पाद राजकपोतासन शामिल हैं। वहीं जो पिछले रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी है, उनमें सेतुबंध सर्वांगासन, सर्वांगासन, वीरभद्रासन व उत्कटासन शामिल हैं।

हिमालय सिद्ध अक्षर बताते हैं कि योग के इस महाकुंभ में करीब साठ देशों के योग साधक भाग लेगें। फिलहाल इसमें अमेरिका, जर्मनी,फ्रांस, यूरोप के बाकी कुछ देशों से स्विट्जरलैंड, लंदन, नीदरलैंड,जापान, मलेशिया, ताइवान सिंगापुर के प्रतिभागियों ने भाग लेना सुनिश्चित किया है। इन देशों के लगभग पांच-पांच सीनियर टीचर मूव करेंगे। ये सीनियर योग शिक्षक हैं। वहीं ट्रेंड योग साधकों की संख्या दो हजार के करीब है।। पिछले बीस दिन तथा आने वाले साठ दिन साधक बारह आसनों का अभ्यास करेंगे। अस्सी दिनों की ट्रेनिंग हैं। स्थानीय प्रतिभागियों में कर्नाटक स्टेट पुलिस, सीआईएसएफ, आर्मी व इंडियन एयर फोर्स के प्रतिभागी पैलेस ग्राउंड बंगलूरू मुख्य आयोजन का हिस्सा होंगे। तीन ऑफिशियल एग्जेबेटर, सौ प्लस गिनीज बुक टीम के एग्जामनर की तरह मूल्यांकन करेंगे। इसके अलावा दस न्यूट्रल टीचर होंगे जो न हमारे होंगे और न गिनीज बुक रिकॉर्ड टीम के। ये बाकी संस्थाओं के चुने जाते हैं। ये इन्होंने किया।

दरअसल, गिनीज बुक रिकॉर्ड की टीम कई महीने पहले से तैयारी करती है इस तरह के रिकॉर्ड दर्ज करने की। एक पूरा एग्रीमेंट बनाया जाता है। 90 दिन पहले प्रोसेस शुरू होता है। बाकायदा लाइसेंस इश्यू किए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि अक्षर योग केंद्र के खाते में इससे पहले 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। डेढ़ दशक पहले स्थापित अक्षर योग केंद्र इस समय आयुष योग इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेशन बॉडी में शामिल है। इसे योग इंस्टीट्यूट की कैटेगरी दी गई है।

यह पूछे जाने पर कि इस तरह के रिकॉर्ड दर्ज कराने का मकसद क्या है। हिमालय सिद्ध अक्षर कहते हैं कि ये रिकॉर्ड एक खेल की तरह हैं, एक आनंद की तरह हैं, एक प्रेम है और एक चैलेंज है। स्पष्ट सी बात है कि जब तक कोई आसनों का अभ्यास नहीं करेगा तो आसन की शक्ति नहीं समझेगा। इसकी यौगिक ताकत नहीं समझेंगे। जब साधक वीरभद्रासन करेगा, तो होल्ड करने पर इसका प्रभाव पता चलेगा।

हमने योग के ज्ञान को अपने आराम के अनुसार ढालने की कोशिश की है। यदि व्यक्ति तपस्या करेगा, मेहनत करेगा तो ही इसका लाभ मिलेगा। इस तरह आसन को करने का चैलेंज है। जैसे पहले हठयोग में होता था। यदि कोई व्यक्ति पदमासन नहीं कर पा रहा है तो साइंटिफिक तरीके से करने की जरूरत है। मेहनत करने की जरूरत है। हम केवल फिलॉसफी के रूप में ही आसनों को सीख रहे हैं। हम इसका पारंपरिक अभ्यास करें। कोई प्रतिभागी समय लगाकर दो महीन तक गरुड़ आसन करे,तो वह अपने शरीर के निचले हिस्से की बीमारियां ठीक कर पाता है। ऐसे ही सर्वांगासन है, समय अनुसार होल्ड करने से शरीर को लाभ मिलता है।

भगवान् श्री परशुराम जयंती

डॉ.परविंदर शर्मा

भगवान् श्री परशुराम जी पीठ अध्यक्ष, जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, पटियाला

जिनकी दृष्टि में जो अन्याय करे, वह दंड के योग्य

भा रतीय संस्कृति में जब भी धर्म, न्याय और मर्यादा की रक्षा की बात होती है, तब-तब कुछ विशेष व्यक्तित्व उदित होते हैं। ऐसे ही एक अद्वितीय पुरुष हैं भगवान परशुराम। वे न केवल ब्राह्मणत्व के प्रतीक हैं, बल्कि क्षत्रिय धर्म के भी परम अधिष्ठाता माने जाते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य किसी एक सम्प्रदाय, जाति या वर्ग की रक्षा नहीं था, बल्कि सम्पूर्ण मानवता, समस्त धर्मों और जीवन मूल्यों की रक्षा था। इसी कारण वह 'सर्वधर्म के संस्थपक' कहे जा सकते हैं। भगवान परशुराम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। वे ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। ब्रह्मर्षि होते हुए भी उनमें क्षत्रिय तेज था। उनका नाम 'राम' पड़ा, और 'परशु' (कुल्हाड़ी) उनके मुख्य शस्त्र होने के कारण वे 'परशुराम' कहलाए। वह विष्णु के छठे अवतार हैं और उन्हें चिरंजीवी माना गया है।

उनका जन्म किसी धर्म विशेष की स्थापना के लिए नहीं, बल्कि धर्म की पुर्नस्थापना, अधर्म के विनाश और समता के प्रचार हेतु हुआ था। उनकी दृष्टि में न कोई ऊँचा था, न नीचा, जो अन्याय करे, वह दंड के योग्य था, चाहे वह कोई भी हो। भगवान परशुराम का व्यक्तित्व अत्यंत शक्तिशाली, करुणामय, तेजस्वी और न्यायप्रिय था। उनके चरित्र में वीरता, तपस्या, ज्ञान, और सेवा भाव का अनुपम संगम था। वे कठोर अनुशासनप्रिय थे लेकिन साथ ही करुणा और सेवा के प्रतीक भी थे। उनका जीवन संत और सैनिक का एक दुर्लभ समन्वय था। उनकी महानता इसी में है कि वे धर्म की रक्षा करते हुए कभी पक्षपाती नहीं हुए। जब-जब अधर्म ने किसी भी धर्म, जाति, वर्ण या सम्प्रदाय में सिर उठाया, उन्होंने उसे बिना संकोच दंडित किया। यही गुण उन्हें 'सर्वधर्म के संस्थापक' की उपाधि दिलाता है।

धर्म की रक्षा में परशुराम की भूमिका का मुख्य रूप रहा है जैसे क्षत्रिय अहंकार के विरुद्ध संघर्ष हम कह सकते है कि जब राजा सहस्त्रबाहु और उनके वंशजों ने धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन किया, ब्राह्मणों और आम जनता पर अत्याचार किए, तब परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। यह कोई जातीय हिंसा नहीं थी, बल्कि अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध एक दैवीय कार्यवाही थी। उन्होंने हर बार दुष्टों को दंड दिया, लेकिन धर्मनिष्ठ क्षत्रियों का सम्मान बनाए रखा। ब्राह्मणत्व की गरिमा की रक्षा जब उनके पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या अहंकारी क्षत्रियों द्वारा की गई, तो परशुराम ने उसका प्रतिशोध लिया। लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि सभी क्षत्रिय अधर्मी हैं। उनका उद्देश्य ब्राह्मणों की गरिमा की रक्षा के साथ-साथ संपूर्ण धर्म व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखना था। स्त्री सम्मान के रक्षक माता रेणुका का जीवन भी परशुराम के जीवन में एक आदर्श बना। यद्यपि एक बार उन्होंने पिता की आज्ञा पर माता का वध किया, किन्तु जैसे ही उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ, उन्होंने माता को पुनर्जीवित किया। यह प्रसंग इस बात को दर्शाता है कि वे स्त्री सम्मान के प्रति संवेदनशील थे। सबके धर्म और आस्थाओं के लिए समान दृष्टिकोण परशुराम ने कभी किसी विशेष सम्प्रदाय को प्राथमिकता नहीं दी। वे ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय धर्म की रक्षा करते थे, और क्षत्रिय होते हुए ब्राह्मण धर्म का पालन करते थे। इस के इलवा समाज के अन्य वर्गों को भी शिक्षा का ज्ञान दिया और साथ ही सल्फ़ के लिए शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया यही कारण है कि वे सभी धार्मिक समुदायों के संरक्षक के रूप में देखे जाते हैं। उन्होंने मानव मात्र के लिए धर्म की अवधारणा को स्थापित किया। परशुराम का विचार था कि धर्म वह है जो सबको समान दृष्टि से देखे। उन्होंने कभी किसी पूजा-पद्धति, आचार-विचार, जाति-धर्म में भेद नहीं किया। उनके अनुसार जो सत्य के पथ पर चलता है, वही धार्मिक है। इस दृष्टिकोण से वे हिन्दू धर्म ही नहीं, बल्कि सनातन के सभी शाखा-प्रशाखाओं के संरक्षक बने। उनकी शिक्षाएं यह बताती हैं कि वे किसी भी मत, पंथ या सम्प्रदाय के विरोधी नहीं थे। वे केवल अधर्म और अन्याय के विरोधी थे। भगवान परशुराम एक महान आचार्य भी थे। उन्होंने कई महान योद्धाओं और राजाओं जिन का समाज के लिए योगदान रह सकता है सब को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी, जिनमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महापुरुष शामिल हैं। वे शिक्षा के माध्यम से धर्म का विस्तार करते थे। उनका गुरुकुल जातिवाद से परे था–जो योग्य था, वही शिष्य बन सकता था।

आज जब समाज धर्म, जाति और सम्प्रदाय के नाम पर विभाजित होता जा रहा है, तब परशुराम का आदर्श मार्गदर्शक बन सकता है। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि –

धर्म का अर्थ केवल पूजा-पद्धति नहीं, बल्कि न्याय, सत्य और समभाव है।

अन्याय करने वाला कोई भी हो, उसका प्रतिरोध करना ही धर्म है।

शिक्षा और ज्ञान का प्रचार ही समाज का सच्चा उत्थान है।

महिलाओं का सम्मान, प्रकृति की रक्षा और संतुलित जीवन जीना ही धर्म का सार है।

हम अंत में कह सकते है कि भगवान परशुराम का जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म की रक्षा केवल किसी एक सम्प्रदाय या वर्ग की सेवा से नहीं होती, बल्कि सभी के कल्याण, न्याय और समानता की भावना से होती है। वे न तो किसी जाति विशेष के प्रतिनिधि थे, न ही किसी एक विचारधारा के। वे मानवता के प्रतिनिधि थे। आज के युग में, जब धर्म को संकीर्णता और विभाजन के उपकरण के रूप में उपयोग किया जा रहा है, तब परशुराम का समतामूलक, न्यायप्रिय और निष्पक्ष दृष्टिकोण हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। वे सही अर्थों में 'सर्वधर्म' हैं–ऐसे रक्षक जो किसी एक धर्म के नहीं, बल्कि सभी धर्मों, सभी जीवन मूल्यों, और समस्त जीवों की रक्षा के लिए अवतरित हुए।

ट्रैवलॉग

ब्रजेश कानूनगो

लेखक स्तंभकार हैं।

इथियोपिया की जनजातियों की अनोखी जीवन शैली

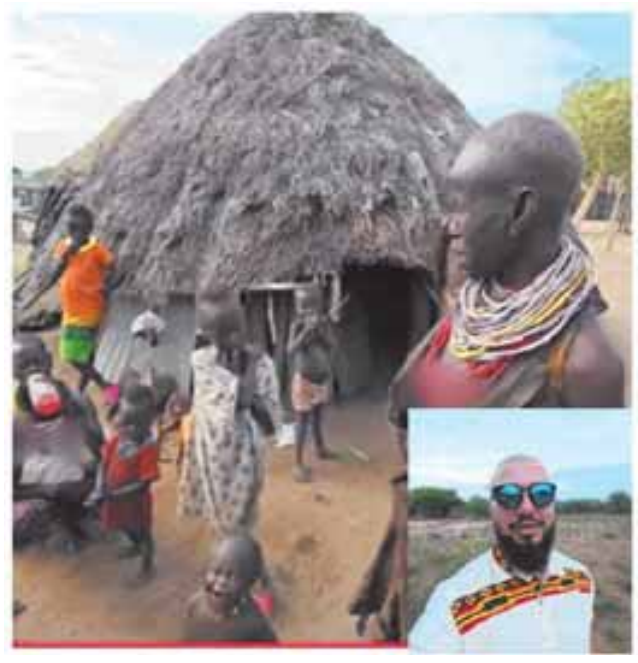

गत दिनों हमने इथियोपिया के जनजातीय क्षेत्रों की मानस यात्रा की।

यूट्यूब के कुछ ट्रैवल विडियोज हमारी इस यात्रा के माध्यम बने।

दक्षिण अफ्रीका का इथियोपिया काफी जैसे लोकप्रिय पेय पदार्थ का जनक रहा है। यहां काफी सेवन को आमतौर पर परंपरागत रूप से सेलिब्रेट भी किया जाता है। ट्रैवलर दावूद अखुंदजादा के साथ हमने सड़क किनारे इथोपियाई महिलाओं द्वारा संचालित स्टाल पर इसकी संपूर्ण प्रक्रिया या रस्म को कुतुहल से देखा। कॉफी बीजों को तवे पर सेका जाना, उसको मूसल से कूटकर पावडर बनाना, परंपरागत केतली में काफी को धीरे धीरे उबाला जाना, कॉफी बीज की धूप देकर उसके धुएं से वातावरण को महकाना, फिर परंपरागत चीनी प्याले में गर्म कॉफी में खुशबूदार वनस्पति डाल के पेश करना। यह सब देखना अद्भुत आनंद और जायके से भर देता है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में दावूद के संग वहां के जीवन का डिजिटल आनंद लेना सचमुच इथियोपिया पहुंच जाने जैसा ही था। हमने विकसित होते आधुनिक इलाकों, परंपरागत छोटे बड़े बाजारों के अलावा इथियोपिया के जनजातीय क्षेत्रों की भी मानस यात्रा की। दावूद के विडियोज के अलावा एक और प्रिय ट्रैवलर बंसी विश्नोई Bansi Bishnoi vlog के भी कुछ विडियोज का अवलोकन किया। बात आज इथियोपिया की जनजातियां की कर लेते हैं, जो हमने अनेक ट्रैवल विडियोज और इंटरनेट की कुछ वेबसाइटों से जुटाई है।

विश्वभर में जनजातियां पर्यटकों को सदैव आकर्षित करती रहीं हैं। जनजाति पर्यटन, संस्कृति और इतिहास के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देता है। कई जगहें और बस्तियों को विशेष रूप से इस विशेष पर्यटन के लिए विकसित किया गया है, जहाँ पर्यटक जनजातीय जीवनशैली, कला, नृत्य, संगीत और रीति-रिवाजों का अनुभव कर सकते हैं।

इथियोपिया इस जनजातीय दृष्टिकोण से भी अनुभवों और सांस्कृतिक परंपराओं का खजाना है। यह दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है, जहाँ मानव गतिविधि लाखों साल पुरानी है। जहां अभी भी बड़ी संख्या जनजातियां अपनी पुरानी परंपराओं और परंपरागत जीवनशैली में निवास करती हैं। जनजातियाँ सदियों से इथियोपियाई परिदृश्य का हिस्सा रही हैं, जहाँ उन्होंने अपने चुनौतीपूर्ण परिवेश के अनुकूल ढलने के लिए अपने साधन और उपाय विकसित किए हैं।

इथियोपिया में 80 से अधिक अलग-अलग जातीय समूह हैं, जो विभिन्न जनजातियों के रूप में जाने जाते हैं। अनेक पर्यटन कंपनियों, टूर एजेंसियों सहित स्थानीय स्तर पर भी अनेक गाइड पर्यटकों को इस लोक संस्कृति और इस परिदृश्य से रूबरू करवाने में संलग्न हैं। खासतौर से ओमो घाटी की गहराई में ये परंपराएँ और समुदाय जीवंत हो उठते हैं। रंग-बिरंगी पृष्ठभूमि, आदिवासी समारोह और कुछ शानदार कला रूपों ने इथियोपिया के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को आकर्षक बना दिया है। मुर्सी, बोडी,सूरी,हमार,दासानाच,कारा आदि कई ऐसी जनजातियां हैं जिनकी अपनी अनूठी संस्कृति और जीवन शैली है। लगभग सभी जनजातियाँ भाषा, कपड़े, भोजन और परंपराओं में भिन्न हैं, जो इथियोपिया में कई सदियों से विद्यमान हैं। मुर्सी ओमो घाटी की सबसे प्रसिद्ध जनजातियों में से एक है, जिसकी आबादी लगभग 8,000 है। उन्हें पारंपरिक रूप से प्रवासी या घुमंतू समुदाय के रूप में जाना जाता है, ये केवल शुष्क मौसम में ओमो के किनारों को छोड़कर बरसात के मौसम में घास के मैदानों में जाते हैं। मुर्सी मवेशियों को काफी महत्व देते हैं, जिनकी संख्या के आधार पर संपन्नता और आदान-प्रदान से अधिकांश रिश्ते, जैसे विवाह, आदि निर्धारित होते हैं और उनका आहार भी मवेशियों पर ही आधारित होता है। ये लोग सुरमिक भाषा बोलते हैं, जो नीलो-सहारन भाषा परिवार से आती है।

मुर्सी महिलाओं के पहनावे से उनकी पहचान सुनिश्चित होती है। सबसे खास और पहचानी जाने वाली विशेषता उनके निचले होठों में सजावटी मिट्टी की डिस्क (देभिन्या) पहनना है, जो सुंदरता और वयस्कता का प्रतीक है। जब कोई लड़की अपनी किशोरावस्था में होती है, तो उसके निचले होंठ को काट दिया जाता है और मिट्टी की डिस्क के साथ तब तक खुला रखा जाता है जब तक कि यह ठीक न हो जाए। फिर इस कट को हर बार नई और अधिक मिट्टी की डिस्क डालकर कई महीनों तक धीरे-धीरे खींचा जाता है,प्रत्येक महिला यह तय करती है कि उसे अपने होंठ को कितना फैलाना है। पुरुष और महिलाएं अपनी सामर्थ्य और शक्ति सिद्ध करने के लिए द्वंद्व युद्ध जैसी कई पारंपरिक रूढ़ खेल प्रतियोगिताओं का सामना करते हैं। इसमें पुरुष लाठियों और महिलाएं धातु के कंगनों का हथियारों के रूप में उपयोग करती हैं।

बोडी जनजाति मुर्सी जनजाति के पड़ोसी हैं, और दोनों समूह अक्सर व्यापार करते हैं। वे चरवाहे लोग हैं जो मवेशियों को बहुत महत्व देते हैं और आम तौर पर खेती की प्रथाओं में भाग नहीं लेते हैं,

इसके बजाय आदिवासी बाजारों में मक्का और अन्य कृषि उत्पादों के लिए व्यापार करना पसंद करते हैं। वे खानाबदोश समुदाय हैं, जो भूमि की कमी को रोकने और अपने मवेशियों के लिए नए चरागाह क्षेत्र खोजने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनके जीवन में मवेशियों के महत्व के कारण, बोडी का मुख्य आहार भी मवेशियों पर केंद्रित है। इस जनजाति के लोग छह महीने तक एक कमरे में रहकर खून और दूध का सेवन करते हैं। यहां के आदिवासी लोग जानवर का खून और दूध एक साथ मिलाकर पीते हैं, जिससे यह कम से कम समय में अधिक मोटे हो सके। यह प्रक्रिया पूरे छह महीने तक दोहराई जाती है, जिससे शख्स की अच्छी सेहत बन सके। वहीं, इसके अलावा भी यह अन्य चीजों का सेवन करते हैं। बोडी पुरुष कपड़े की स्कर्ट पहनते हैं, जबकि महिलाएं बकरी की खाल से बने कपड़े पहनती हैं। पुरुष और महिला दोनों ही विशिष्ट रस्म में हिस्सा लेते हैं, जिसका इस्तेमाल व्यक्तियों की सुंदरता और साहस दिखाने के लिए किया जाता है। ये लोग मोटा होना अच्छा मानते हैं और इसके लिए कई उपाय करते हैं। छह माह वसायुक्त भोजन कर शारीरिक श्रम बंद करके अपना वजन बढ़ाते हैं। इस जनजाति में, मोटा होना बहुत आकर्षक माना जाता है और इसलिए महिलाएँ भी संभावित पतियों की तलाश के लिए इस उद्देश्य से आयोजित एक समारोह का उपयोग करती हैं

कारा एक अर्ध-खानाबदोश जनजाति है, कारा पहले चरवाहे थे जो मवेशियों पर निर्भर थे, बाद में परिस्थितियों वश उन्होंने मकई, सेम और कद्दू उगाने के लिए कृषि तकनीक विकसित की। उनके पास मछली पकड़ने का एक अनूठा तरीका भी है, जिसमें मछलियों को छेदने के लिए लंबे भाले का इस्तेमाल किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि केवल अविवाहित युवा पुरुष ही मछली पकड़ सकते हैं, और उन्हें बाद में शुद्धिकरण अनुष्ठान करना होगा क्योंकि मछली पकड़ना पहले वर्जित माना जाता था।

इनके गांव शंकु के आकार की झोपड़ियों से बने हैं, जो लकड़ी के खंभों को आपस में बुनकर बनाई गई हैं और मिट्टी से ढकी हुई हैं, और छतें पुआल की हैं। झोपड़ियों में लकड़ी के खंभों से बने 'दरवाजे' हैं, जहाँ वे घर के प्रतीकात्मक प्रवेश द्वार के रूप में भैंस के कान या खुर जैसी वस्तुएँ लटकाते हैं। कपड़े साधारण होते हैं। केश सज्जा कारा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें पुरुषों के बालों को लट में बांधा जाता है, रंगा जाता है और मोतियों, पंखों और फूलों से भिन्न शैलियों में सजाया जाता है।

कारा अपने शरीर को सफेद चाक, काले कोयले और पीले और लाल खनिजों का उपयोग करके डिज़ाइनों से रंगते हैं। वे निशान बनाने की प्रथा भी अपनाते हैं, जिसमें त्वचा को जानबूझकर काटा जाता है ताकि एक उभरा हुआ निशान प्रभाव पैदा हो जो महिलाओं के लिए एक सौंदर्य अपील के रूप में देखा जाता है, और पुरुषों की उपलब्धियों का संकेत देता है जैसे कि किसी दुश्मन या खतरनाक जानवर को मारना।

ओमो घाटी की अधिकांश जनजातियों में कपड़े और अलंकरण महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मूल्य रखते हैं। महिलाओं के लिए, सामाजिक स्थिति उनके द्वारा पहने जाने वाले मोतियों के हार की संख्या और रंग से प्रदर्शित होती है, लड़कियों को उनका पहला हार उनके पिता द्वारा दिया जाता है और फिर हर साल नए जुड़ते जाते हैं, जिन्हें कभी नहीं उतारा जाता है। पुरुषों के लिए, नुकीले धातु के छल्ले और कटे हुए किनारों वाले कंगन रक्षात्मक हथियार के रूप में उपयोग के लिए पहने जाते हैं, और निशान योद्धा के रूप में उनकी उपलब्धियों को दर्शाते हैं।

हमारे ट्रैवल ब्लॉगरों के हम जैसे दर्शक हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे जिनकी बदौलत घर बैठे इस अनोखी दुनिया के लोगों, रीति रिवाजों और जीवन शैली को जानने समझने का मौका मिल जाता है। शुभकामनाएं है कि वे खूब यात्राएं करें, उनके कैमरों से हमें नई दृष्टि और रचनात्मक समझ भी मिलती रहे।

बाल विवाह न हो, इसके लिए प्रशासन की रहेगी नजर, अक्षय तृतीया को लेकर बाजारों में बढ़ी भीड़

अक्षय तृतीया पर जिले में होगी करीब एक हजार से अधिक शादियां, 100 से ज्यादा मैरिज गार्डन हुए बुक

बैतूल। अक्षय तृतीया पर इस बार जिले में एक हजार से अधिक शादियां होगी। जगह-जगह सामुदायिक विवाह संपन्न कराये जायेगे। वहीं निजी शादियों की तिथि भी है। इसके लिए शहर के मैरिज गार्डन-कैटरिंग, घोड़े, बैंड, डीजे की बुकिंग फुल हो चुकी है। बाल विवाह न हो, इसके लिए जिला प्रशासन की नजर रहेगी। रसोईये से लेकर टेंट, गार्डन, पंडित सबकी जिम्मेदारी रहेगी कि वे बाल विवाह न तो करवाए और न ही उनमें शामिल हो। मई से जून तक विवाह के 31 शुभ मुहूर्त हैं। लेकिन इनमें सबसे खास 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का मुहूर्त रहेगा। एक ही दिन में करीब एक हजार जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे। पंडित के अनुसार इस बार अक्षय तृतीया पर शुभ अमृत योग, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। इसके अलावा वैशाख शुक्ल तृतीया, रोहिणी नक्षत्र शोभन योग, मेष के सूर्य वृषभ के चंद्रमा की साक्षी में पूरे विवाह आदि मांगलिक कार्य किए जाएंगे।

शादियों को लेकर बाजारों में दिखाई दे रही चहल-पहल: अक्षय तृतीया पर होने वाली शादियों को लेकर बाजारों में चहल-पहल दिखाई दे रही है। इसके लिए लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़ा, रेडीमेड कपड़े, सोने-चांदी की दुकानों पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। व्यापारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद है। व्यापारियों का कहना है कि जैसे-जैसे अक्षय तृतीया की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे बाजारों में रौनक बढ़ रही है। तापमान 40 डिग्री के आसपास होने के बावजूद भी लोग भरी दोपहरी में बाजार पहुंच रहे है। कपड़ा, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रेडीमेड कपड़े, सोने-चांदी की दुकानों पर सुबह से देर रात तक ग्राहकी देखी जा रही है।

बाल विवाह रोकने प्रशासन ने की तैयारी: अक्षय तृतीया के अबूझ मुहूर्त में बाल विवाह भी होते हैं। जिन्हें रोकने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। महिला एवं बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी गौतम अधिकारी ने बताया कि बाल विवाह रोकने के लिए ब्लाक स्तर पर कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा सहयोगी प्रदीपन संस्था द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि बालिका की 18 वर्ष और बालक की 21 वर्ष आयु होने के उपरांत ही विवाह करे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा भी बाल विवाह रोकने जनजागरूकता अभियान चलाया रहे है। बाल विवाह कराया जाता है तो सूचना मिलने पर विवाह रोका जायेगा।

समाज और परंपरा से जुड़ा पर्व : अक्षय तृतीया को आखातीज या आखा तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। भविष्य पुराण में वर्णित है कि इस दिन किए गए सभी कर्मों का फल अक्षय होता है, इसलिए इसका नाम ही अक्षय तृतीया पड़ा है। मांगलिक कार्यों के लिए यह तिथि अबूझ मानी जाती है, इसलिए लोग विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्य इस दिन कर रहे हैं। इसके चलते बाजारों में सोने-चांदी के साथ-साथ वस्त्र, बर्तन, फर्नीचर और सजावट के सामान की बिक्री में भी भारी उछाल देखने को मिल रहा है। लोग धनतेरस की तरह ही इस दिन को निवेश के अवसर के रूप में देख रहे हैं। इस दिन खरीदी गई वस्तुएं घर में लंबे समय तक बनी रहती हैं और आर्थिक स्थायित्व लाती हैं।

इनका कहना है -

बाल विवाह रोकने के लिए ब्लाक स्तर पर कमेटी बनाई है। इसके अलावा सहयोगी प्रदीपन संस्था और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों को बाल विवाह न कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सारणी क्षेत्र से बाल विवाह की सूचना मिली थी, यह विवाह 30 अप्रैल को होना था, जिस पर वर-वधु दोनों पक्षों को बाल विवाह न कराने समझाईश दी, दोनों पक्ष मान गये है। यदि कहीं से भी बाल विवाह की सूचना मिलती है तो त्वरित कार्यवाही करेंगे।

गौतम अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग बैतूल

हार्टफुलनेस सामूहिक ध्यान कार्यक्रम कल 30 अप्रैल को

प्रशिक्षक डॉ. गोरख सर की उपस्थिति में होगा कार्यक्रम

बैतूल। हार्टफुलनेस के माध्यम से अब बैतूल के निवासी भी ध्यान की उन चार विधियों से जुड़ेंगे, जो जीवन को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ बनाती है और व्यक्ति के जीवन को तनाव रहित भी करती है। कल बुधवार 30 अप्रैल से वृंदावन नगर रानीपुर रोड स्थित हार्टफुलनेस ध्यान केंद्र पर सुबह 8ः30 बजे से हार्टफुलनेस ध्यान की शुरुआत हो रही है। यह शुरुआत हार्टफुलनेस के संस्थापक परमपूज्य बाबूजी महाराज के 126वीं जन्मदिवस के अवसर पर की जा रही है।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी देने के लिए हार्टफुलनेस बैतूल केंद्र द्वारा सोमवार दोपहर को शहर के होटल जायका में दोपहर 3:30 बजे से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था जिसमें केंद्र के कमलनयन अग्रवाल ने बताया कि हार्टफुलनेस ध्यान की चार विधियां हैं, पहली विधि रिलैक्सेशन की है जिसके माध्यम से सबसे पहले हम अपने शरीर को रिलैक्स मुद्रा में लाते हैं। जिससे हमारा शरीर शिथिल हो जाता है, तत्पश्चात् हम दूसरी प्रक्रिया अर्थात ध्यान में बैठ जाते हैं। ध्यान में बैठने के पहले हम अपने मन में एक विचार लेते हैं कि मेरे हृदय में एक ईश्वरी प्रकाश मौजूद है, जो मुझे अपनी और आकर्षित कर रहा है। यह विचार लेकर हम अपना ध्यान हृदय पर केंद्रित करके अपनी आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। इस प्रकार से जब तक हम सहज महसूस करते हैं, तब तक ध्यान मुद्रा में बैठकर ध्यान करते हैं। हार्टफुलनेस में यह प्रक्रिया हार्टफुलनेस के प्रशिक्षक की उपस्थिति में कराई जाती है। शाम को जब हम अपने कामों से लौट कर घर आते हैं, तब हमें सफाई जिसे क्लीनिंग भी कहते हैं कि प्रक्रिया करनी होती है, यह प्रक्रिया बहुत ही प्रभावशाली है। जिसे हम घर पर या ध्यान केंद्र पर कहीं भी एकांत में बैठकर करते हैं। अंत में जब हम अपने बिस्तर पर सोने चले जाते हैं, तब हम एक छोटी सी प्रार्थना करते है जिससे हमारी नींद गहरी होती है। इस प्रकार उन्होंने हार्टफुलनेस ध्यान की चार विधियां बताई। हार्टफुलनेस ध्यान एक सहज ध्यान है, जिसे कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर किसी भी समय एक बार प्रशिक्षक से सीखकर कर सकता है। हार्टफुलनेस ध्यान में एक तकनीक जिसे प्राण आहुति कहा गया है, पर जोर दिया जाता है। इसमें हार्टफुलनेस के प्रति शिक्षक अभ्यासी को अपने सामने बिठाकर प्राण आहुति के माध्यम से सेटिंग देते हैं। जिससे अभ्यासियों को ध्यान करने में काफी मदद मिलती है। प्रशिक्षण के अभ्यासी को अपनी अंदर से ऊर्जा मिलती हैं जिसे प्राण होती कहा जाता है। 30 अप्रैल को आयोजित इस सामूहिक ध्यान कार्यक्रम का आयोजन बैतूल केंद्र की ओर से संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम में हार्टफुलनेस हरदा के प्रशिक्षक डॉ. गोरख सर के निर्देशन में ध्यान करवाया जाएगा।

हादसे ने छीना पैर, हौसले ने दिलाए मेडल

मुलताई के सतीश ने नेशनल पैरा चैंपियनशिप में जीता रजत पदक

बैतूल। टूटे सपनों को फिर से जोडऩे की ताकत अगर किसी में होती है, तो वह है जज्बा। बैतूल जिले के मुलताई तहसील के रहने वाले सतीश बिंझाडे ने इसी जज्बे की मिसाल कायम की है। वर्ष 2019 में एक भीषण ट्रेन हादसे ने उनका बायां पैर घुटने के नीचे से छीन लिया, लेकिन उनके सपनों और हौसलों को नहीं तोड़ सका। जहां आमतौर पर ऐसे हादसे ज़िंदगी की रफ्तार थाम देते हैं, वहीं सतीश ने अपनी कश्ती को नए साहसिक सफर पर मोड़ दिया। उन्होंने खुद को चुनौती दी और एडवेंचर स्पोर्ट्स में कदम रखा। लेह-लद्दाख की बर्फीली चोटियों से लेकर ऊंचे पर्वतों और कठिन मैराथनों तक, सतीश ने हर चुनौती को पार किया और अपनी कामयाबी का परचम लहराया। आज सतीश भोपाल स्थित मध्यप्रदेश वॉटर स्पोर्ट्स अकादमी में कोच पीजूस कांति बरोई के मार्गदर्शन में पिछले दो वर्षों से कठिन ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसी मेहनत का नतीजा रहा कि भोपाल में आयोजित 18वीं नेशनल पैरा कैनोइंग चैंपियनशिप 2024-25 में उन्होंने मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में मनीष कोरव ने स्वर्ण पदक जीता और सतीश बिंझाडे ने रजत पदक अपने नाम कर प्रदेश को गर्व से भर दिया। सतीश बताते हैं कि वॉटर स्पोर्ट्स में आने की प्रेरणा उन्हें मशहूर खिलाड़ी प्राची यादव से मिली। प्राची को वे अपना आदर्श और मार्गदर्शक मानते हैं। सतीश का मानना है कि हार मानना किसी भी इंसान की सबसे बड़ी हार होती है। ज़िंदगी कहीं से भी दोबारा शुरू की जा सकती है, बशर्ते हिम्मत और उम्मीद कायम रहे। अब सतीश की नजरें अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप पर हैं। वे दिन-रात मेहनत कर रहे हैं ताकि एक दिन तिरंगे को दुनिया के मंच पर लहरा सकें। सतीश कहते हैं कि उनका सपना है अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना और यह साबित करना कि हौसलों के सामने कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती।

एक युवक ने लड़की का अपहरण कर किया दुष्कर्म, मारपीट कर फरार हो गया.....!

रात में शौच का कहकर गई थी लड़की, सुबह घायल अवस्था में मिली, प्राथमिक उपचार कर किया इंदौर रेफर!

देवास/मोहन वर्मा । जिले के भौंरासा थाना अंतर्गत ग्राम मानकुंड के नौसराबाद में बीती रात को एक लडक़ी का वर्ग विशेष युवक ने अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी लडक़ी को अंधेरे में छोडक़र फरार हो गया था। लडक़ी को घायल अवस्था में आज सुबह चुरलाय फाटे पर देखा वहां से उसे जिला चिकित्सालय उपचार के लिए लेकर आए यहां प्राथमिक उपचार कर उसे इंदौर रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर जिला चिकित्सालय के स्वास्थ्य नोडल अधिकारी, सीएसपी, भौंरासा थाना प्रभारी, कोतवाली थाना प्रभारी सहित पुलिस बल जिला चिकित्सालय पहुंच गया था। मामले को लेकर पुलिस ने वर्ग विशेष युवक के विरुद्ध अपहरण, मारपीट सहित दुष्कर्म की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।

जानकारी के अनुसार भौंरासा थाना अंतर्गत ग्राम मानकुंड के नौसराबाद में बीती देर रात को एक लडक़ी घर से लापता हो गई थी, जो आज सुबह चुरलाय फाटे पर गंभीर घायल अवस्था में मिली थी। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि लडक़ी बीती रात को शौच के लिए गई थी। वहां उसकी चिल्लाने की आवाज आई हम वहां पहुंचे तो वहां लडक़ी नहीं मिली। उसे रात में यहां-वहां तलाशते रहे। हमारे पड़ोसी सुबह प्याज काटने के लिए चुरलाय आए थे उसने बताया कि एक लडक़ी चुरलाय फाटे पर मिली है, परिजन वहां पहुंचे वहां एंबुलेंस से देवास लेकर आए। परिजनों ने बताया कि एक युवक मानकुंड का रहने वाला शौकत मंसूरी है। सुबह चुरलाय फाटे के समीप लडक़ी मिली उसे वहां से जिला चिकित्सालय लेकर आए जहां उसका प्राथमिक उपचार कर इंदौर रेफर किया गया। इस मामले को लेकर सीएमएचओ ने बताया कि लडक़ी के सिर पर व चेहरे पर चोंट के निशान है। इसलिए उसे रेफर किया गया है। मामले को लेकर भौंरासा थाना प्रभारी प्रीति कटारे ने आरोपित के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया है।

भाजपा जिलाध्यक्ष रायसिंह सेंधव सूचना मिलने पर जिला चिकित्सालय पहुंचे उन्होंने कहा कि मैं पीड़िता को देखने आया था, पीड़िता गंभीर घायल है। जिसने भी यह कृत्य किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता अजा वर्ग की है उसके साथ इस प्रकार का घटनाक्रम होना दुर्भाग्यपूर्ण है। आरोपित का मकान भी ध्वस्त किया जाना चाहिए।

शासन से शौचालय के लिए कुछ नहीं मिला: पीड़िता की माँ ने बताया कि पीड़िता घर पर ही रहती थी, पढ़ाई बंद कर दी थी। घर में शौचालय नहीं है इसके लिए उन्हें गांव में सुनसान क्षेत्र में जाना पड़ता है। उन्होनें बताया कि उन्हें शासन की और से शौचालय के लिए कुछ नहीं मिला है।

आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए चार टीमें बनाई: इस मामले को लेकर एडिशनल एसपी जयवीर सिंह भदौरिया घटना की जानकारी मिलने पर भौंरासा थाने पहुंचे और घटना के बारे में पूरी जानकारी ली। भौंरासा पुलिस ने आरोपी वर्ग विशेष व्यक्ति के खिलाफ मारपीट, दुष्कर्म और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी को पकडऩे के लिए पुलिस ने चार अलग-अलग टीम बनाई है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। क्षेत्रीय लोग आरोपी के घर को तोडऩे की मांग कर रहे है।

आरोपी के विरुद्ध अपराध किया दर्ज: सीएसपी दीशेष अग्रवाल ने बताया कि भौंरासा थाने की घटना है। एक बालिका को जिला अस्पताल में लाया गया था। पीड़ित की मां द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति उसे रात में ले गया था सुबह वह घायल अवस्था में मिली। जिला अस्पताल में उसका उपचार किया गया। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसकी तलाश की जा रही है। बालिका के चेहरे पर चोट के निशान है इस संबंध में उसका सीटी स्केन करवाया गया और उपचार के लिए उसे इंदौर एमवाय अस्पताल रैफर किया गया। मामला विवेचना में है अग्रीम कार्रवाई की जा रही है।

मुलताई में सड़क पर बिछाया पाकिस्तान का झंडा

बैतूल। मुलताई में कांग्रेस नेता हर्षवर्धन धोटे के नेतृत्व में युवाओं ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बस स्टैंड की मुख्य सडक़ पर युवाओं ने पाकिस्तान के झंडे को बिछाकर अपना आक्रोश जाहिर किया और हाल ही में पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। इस हमले में मारे गए भारतीय टूरिस्टों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रदर्शन के दौरान हर्षवर्धन धोटे ने कहा कि पूरा देश इस आतंकी हमले से आक्रोशित है और दिवंगतों के परिवारों के साथ पूरी तरह खड़ा है। उन्होंने भारत सरकार से मांग की कि सेना को खुली छूट दी जाए ताकि वह पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दे। उन्होंने कहा कि जब तक आतंक के अड्डे खत्म नहीं होंगे, तब तक इस तरह की कायराना हरकत होती रहेंगी। अब वक्त आ गया है कि सख्त जवाब दिया जाए ताकि फिर कभी कोई आतंकी भारत की तरफ आंख उठाकर न देख सके। इस विरोध प्रदर्शन में हर्षवर्धन धोटे के साथ अमरचंद अग्रवाल, वसंत पूरी, राबिन सिंह, सोहेल खान, साहरुख खान और वसीम समेत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्य और कई युवा मौजूद रहे। सभी ने मिलकर पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर संदेश दिया। प्रदर्शन के अंत में सभी उपस्थित युवाओं ने दो मिनट का मौन रखकर आतंकी हमले में मारे गए सभी भारतीयों को श्रद्धांजलि दी और संकल्प लिया कि देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा खड़े रहेंगे।

आंतरिक साधना से ही आत्मसाक्षात्कार संभव, शिमला में हुआ धर्म महासम्मेलन

देवास। शिमला हिमाचल प्रदेश में आनंद मार्ग प्रचारक संघ के तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय धर्म महासम्मेलन (26-27 अप्रैल) के भव्य धर्म महासम्मेलन के द्वितीय दिवस आध्यात्मिक ऊर्जा और उत्साह से परिपूर्ण रहा। प्रातःकालीन सत्र की दिव्यता साधकों द्वारा गुरु सकाश, पांचजन्य एवं सामूहिक साधना में बाबा नाम केवलम महामंत्र कीर्तन से प्रकट हुई, जिससे संपूर्ण वातावरण आध्यात्मिक चेतना से गुंजायमान हो उठा। आनंद मार्ग के पुरोधा प्रमुख श्रद्धेय आचार्य विश्वदेवानन्द अवधूत के आगमन पर आनंद मार्ग सेवादल के समर्पित स्वयंसेवकों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान कर ससम्मान स्वागत किया। जिसमें उज्जैन के वरिष्ठ मार्गी आदरणीय डॉ अशोक शर्मा जी द्वारा प्रत्येक धर्म महासम्मेलन में सेवादल के कार्यकर्ता के रूप में अपनी निःस्वार्थ सेवा देते हैं। आनंद मार्ग प्रचारक संघ देवास के सेवा धर्म मिशन के भुक्ति प्रधान हेमेन्द्र निगम काकू ने बताया कि श्रद्धेय पुरोधा प्रमुख आचार्य विश्वदेवानंद अवधूत ने साधकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्राचीन काल से मानव आत्म-साक्षात्कार हेतु विविध साधनाओं तप, व्रत, यज्ञ, तीर्थयात्रा आदि का आश्रय लेता रहा है। तथापि, शिव और पार्वती के संवाद के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि बाह्य तप, यज्ञ या उपवास के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। वास्तविक मुक्ति केवल मैं ब्रह्म हूँ इस ज्ञान के माध्यम से ही संभव है। भगवान शिव ने यह स्पष्ट किया था कि शरीर को कष्ट देने वाली क्रियाएँ जैसे कठोर तप, दीर्घकालीन उपवास अथवा तीर्थ यात्रा केवल शारीरिक परिश्रम हैं, जो आत्मसाक्षात्कार का साधन नहीं बन सकतीं।

जनहित के प्रति अपने दायित्वों को पूरी ईमानदारी और संवेदनशीलता से निभाएं अधिकारी : कलेक्टर

नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन इत्यादि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

बैतूल। जनहित के प्रति अपने दायित्वों को पूरी ईमानदारी, सेवा भाव और संवेदनशीलता के साथ निभाएं। शासन की सभी योजनाओं सहित अन्य कार्यों का जनसामान्य को समय पर लाभ मिले। यह निर्देश सोमवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने सभी एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ एवं सभी विभागों के अधिकारियों को दिए। जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा कर कलेक्टर ने सभी जनपद सीईओ, सीएमओ और कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यंत्री सेवा को निर्देश दिए कि अभियान के तहत ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के सभी तालाबों और अन्य जल स्त्रोतों के मरम्मत और स्वच्छता के कार्यों में गति लाएं। इसी प्रकार चेक डैम, ग्रे वॉटर, रिचार्ज संरचनाओं के निर्माण में भी तेजी तेजी लाए। उन्होंने नहरों की साफ सफाई और किलोमीटर स्टोन भी लगाने के निर्देश कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग को दिए। उन्होंने उद्यानिकी विभाग को जन जागरूकता के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को रिचार्ज शॉप का निर्माण शीघ्र कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी जल संरचनाओं पर हुए अतिक्रमण को भी तत्काल हटवाएं। सभी एसडीएम अपने क्षेत्र में विकासखंड स्तर पर भी विभागवार अभियान की मॉनिटरिंग करें।

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी अधिकारी अपनी विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कराएं। पेंशन के कोई भी प्रकरण लंबित न रहें। छात्रावासों में स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। नामांतरण, बटवारा इत्यादि राजस्व प्रकरणों का भी शीघ्र निराकरण कराएं। मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, सडक़ सुधार इत्यादि शिकायतों का भी त्वरित निराकरण किया जाए। नगरीय निकायों में भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। किसान सम्मान निधि के राशि भुगतान में विलम्ब न हो।

संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की भूख हड़ताल शुरू

2 मई को भोपाल घेराव की चेतावनी

बैतूल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिले के लगभग 850 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल सोमवार 28 अप्रैल को लगातार सातवें दिन भी जारी रही। कर्मचारियों ने आंदोलन को और तेज करते हुए क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष डॉ. गोविंद साहू ने बताया कि प्रदेशभर में 32 हजार संविदा कर्मचारी पिछले 20 वर्षों से स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। कोरोनाकाल जैसी भीषण महामारी में भी इन कर्मचारियों ने अपने परिवारों और जान की परवाह किए बिना सेवा दी थी। इसके बावजूद आज तक उनकी मांगों पर समुचित कार्रवाई नहीं हुई है। डॉ. गोविंद साहू ने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 जुलाई 2023 को भोपाल में आयोजित महापंचायत में संविदा कर्मचारियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की थीं। इन घोषणाओं के पालन में सामान्य प्रशासन विभाग ने 23 जुलाई 2023 को संविदा कर्मचारियों के लिए एक नई नीति लागू की थी। लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल द्वारा दी गई सुविधाओं में कटौती कर दी गई, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश है। संघ के अनुसार विभाग में रिक्त पदों पर संविलियन कर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। पहले से दी जा रही सुविधाओं में ईएल और मेडिकल अवकाश को अलग कर दिया गया है। अनुबंध प्रक्रिया को पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया है और अप्रेजल की व्यवस्था अब भी जारी है। सेवानिवृत्ति की उम्र को भी 65 वर्ष से घटाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। इसके साथ ही कर्मचारियों को एनपीएस, ग्रेच्युटी, स्वास्थ्य बीमा और डीए जैसी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। संघ ने मांग की है कि शासन वेतन समकक्षता में पुनर्विचार कर संशोधन करे और गलत तरीके से निष्कासित किए गए सपोर्ट स्टाफ एवं मलेरिया एमपीडब्ल्यू कर्मचारियों की एनएचएम में वापसी कराई जाए। संघ ने चेतावनी दी कि यदि शासन ने जल्द ही कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना तो 2 मई 2025 को प्रदेश के समस्त 32 हजार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भोपाल स्थित एनएचएम कार्यालय का घेराव करेंगे।

पेंशनर संघ, 60 प्लस लालबाग ग्रुप के वरिष्ठ सदस्यों ने पूर्व विधायक से धार के इतिहास पर की चर्चा

धार। पेंशनर संघ व 60 प्लस लालबाग ग्रुप के वरिष्ठ सदस्यों ने धार के पुर्व विधायक करणसिंह पवार से सहज मुलाकात में वरिष्ठजनों ने विक्रम ज्ञान मंदिर में वाचनालय - पुस्तकालय व धार में बेडमिंटन की शुरुआत सहित कई विषयों पर चर्चा कर पूरानी यादें ताजा हो गई। धार के इतिहास पर चर्चा से ऐतिहासिक नगरी धार की अतीत की स्मृतियाँ ताजा हो गई । वरिष्ठजन किशोरीलाल डांगी, आंनदी लाल जी, उदयजी, कैलाश बैरागीजी, कैलाश मालवीया जी, मधुकर कुंठे जी, महेश माहेश्वरी, नारायण कुबेर जोशी ,बी एल गोयल , दामोदर यादव, नारायण राव घाटे, नरवर सिंह जी सभी वरिष्ठ सदस्यों ने करण सिंह पवार के साथ संवाद कर अपने विचारों से अवगत कराया।

ग्रामीण एकल नल-जल प्रदाय योजना की सभी बाधाओं को दूर करते हुए तत्काल संचालन प्रारंभ कराएं : उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल

उप मुख्यमंत्री ने रीवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण एकल नल-जल योजना की समीक्षा की

भोपाल । उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि रीवा विधानसभा क्षेत्र की ग्रामीण एकल नल-जल योजना की सभी बाधाओं का निराकरण करते हुए तत्काल संचालन प्रारंभ कराएं। उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित पंचायतों के सरपंच के साथ बैठक कर जल प्रदाय की समस्याओं को दूर करें तथा एक पखवाड़े में सभी नलजल योजनाओं को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर सुगम संचालन सुनिश्चित कराएं।

रीवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में एकल नल-जल योजना की ग्रामवार समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने जल प्रदाय योजना की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि पाइप लाइन में सुधार, पानी की उपलब्धता, विद्युत कनेक्शन आदि समस्याओं का निराकरण कराएं तथा संबंधित सरपंचों से योजना का संचालन कराएं ताकि घरों में जल प्रदाय समुचित ढंग से होने लगे। उन्होंने रीवा विधानसभा अन्तर्गत 14 ग्राम पंचायतों के 24 ग्रामों में जल प्रदाय के लिए निर्मित एकल नल-जल परियोजना के संबंधित संविदाकारों से पानी की सप्लाई की स्थिति की जानकारी प्राप्त की तथा पीएचई विभाग के कार्यपालन यंत्री को निर्देशित किया कि आवश्यक सुधार कार्य कराकर जल प्रदाय कराएं। उन्होंने कहा कि आगामी 15 दिवस में पुन- बैठक कर की गई कार्यवाही की समीक्षा की जाएगी।

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने बताया कि संबंधित सरपंचों, पीएचई के अधिकारियों तथा सचिव व ग्राम सहायक की समन्वित बैठक में जल प्रदाय की समस्याओं का निराकरण कर घर-घर पानी सप्लाई का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस अवसर पर समाजसेवी राजेश पाण्डेय ने ग्राम पंचायतों में जल प्रदाय की जानकारी दी तथा आवश्यक सुझाव दिए। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल, एसडीएम अनुराग तिवारी, तहसीलदार एवं प्रभारी सीईओ रीवा जनपद शिवशंकर शुक्ला, जल निगम के अधिकारी, पीएचई के सहायक यंत्री, उपयंत्री तथा संविदाकार उपस्थित रहे। पूर्व विधायक करणसिंह पवार से मुलाकात में ऐतिहासिक नगरी धार की अतीत की स्मृतियाँ ताजा हो गई

रेवा साहित्य मंच की मासिक काव्य गोष्ठी सम्पन्न

नरसिंहपुर। रेवा साहित्य मंच की मासिक काव्यगोष्ठी मरहई माता दरबार कौड़िया में चन्द्रभान मालवीय के मुख्यातिथ्य व कविवर भगवत सिंह धानक की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।माँ सरस्वती के पूजन-अर्चन व वरिष्ठ कवि टी.आर.उरधैंया द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वन्दना से काव्य गोष्ठी का शुभारंभ हुआ। सेवानिवृत्त शिक्षक उमाशंकर अग्रवाल ने पहलगाम घटना पर अपने विचार कहे।फाग कवि शंकरलाल बैरागी ने प्रथम मनाऊँ दादा हनुमत रचना सुनाकर वाहवाही लूटी।वरिष्ठ कवि पी.एस.पुराणिया 'पांचाल' ने दुनिया का रखवाला है प्रभु ,डोर सबकी पकड़े रचना कही।गाडरवारा से पधारे काव्य गोष्ठी का संचालन कर रहे शिक्षक कवि मलखान सिंह मेहरा ने चाँद और सूरज धर्म का भेद जानते,रोज रक्त के गोले बरसते सुनाकर वाहवाही लूटी।

संत भूरेलाल के सानिध्य में दूल्हा-दुल्हन ने ली

● जल संरक्षण संवर्धन की शपथ

सुबह सवेरे सोहागपुर । समीपवर्ती आदिवासी ग्राम टेकापार में मध्यप्रदेश जन अभियान सोहागपुर के तत्वावधान में जल गंगा संवर्धन अभियान तहत चौपाल का आयोजन संत भूरेलाल के आतिथ्य में संपन्न हुआ। उल्लेखनीय है कि समाजसेवी संत भूरेलाल गरीब बच्चियों की शादी का संकल्प के साथ सकल समर्थ अभियान के अंतर्गत 21 जोड़ों का विवाह कराया गया था। जिसमें समस्त दहेज सामग्री प्रदान की थी। जन अभियान परिषद के ब्लाक समन्वयक किशोर कड़ोले एवं सदस्यों ने कार्यक्रम से ओत-प्रोत होकर आश्रम में एक अन्य जोड़े का विवाह संत भूरेलाल ने दहेज सामग्री प्रदान की। इस अवसर पर करीबन 150 जन अभियान परिषद के सदस्य बराती एवं घरातियों के साथ ग्रामीण उपस्थित थे। इस अवसर पर दूल्हा दुल्हन को संत भूरेलाल ने जल गंगा संवर्धन की शपथ परामर्शदाता श्याम सिंह मीना ने उपस्थित जनों को दिलाई। इसी अवसर पर उपस्थित जनों को जन अभियान परिषद् का परिचय कराया। और परिषद के उद्देश्य एवं कार्यो से अवगत कराया। तथा जल गंगा संवर्धन तथा संरक्षण पर संगोष्ठी की सभी उपस्थित जनों को भी शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में नवांकुर संस्था नवरंग युवा मंडल संदेश मिश्रा सचिन विश्वकर्मा , समाजसेवी प्रंयाशु राठे, प्रेमनारायण ठाकुर, सुनील राठौर, प्रशांत बसैड़िया व्यवसायिक, पदम कांत ठहरिया, राकेश मालवीय जनपद ऑपरेटर, सरपंच खेत सिंह, सचिव मुन्ना लाल, शिवराम ठाकुर आदि उपस्थित थे

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का मिल रहा है लाभ

● जिले के कृषक रूपराम कौरव हो रहे लाभान्वित

नरसिंहपुर। छोटे एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि किसानों को दी जा रही है। इन्हीं योजनाओं का लाभ जिले की गाडरवारा तहसील के ग्राम भौरझिर के कृषक श्री रूपराम कौरव को भी प्राप्त हो रही है। वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तो मिल रही है। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिल रहा है। कृषक श्री कौरव बताते हैं कि उन्हें लगातार इन योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। यह योजना किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 12 हज़ार रुपये मिलते हैं।यह राशि कृषि गतिविधियों को पूरा करने में मददगार हो रही है।योजनाओं से मिलने वाली राशि खाद-बीज और अन्य कृषि कार्य में काम आ रही है। इसके अलावा वे इन पैसो को जोड़कर अन्य कार्यों में भी इसका उपयोग करते हैं। इस योजना के लिए वे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हैं।

एम्स भोपाल की डॉ. रेखा जिवाने और डॉ. रागिनी श्रीवास्तव ने अमेरिकन फिजियोलॉजी समिट 2025 में प्रस्तुत किया अभिनव शोध

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के सक्षम मार्गदर्शन में फिजियोलॉजी विभाग की अतिरिक्त प्रोफेसर डॉ. रेखा जिवाने एवं डॉ. रागिनी श्रीवास्तव ने एम्स भोपाल का प्रतिनिधित्व प्रतिष्ठित अमेरिकन फिजियोलॉजी समिट 2025 में किया, जो 24 से 27 अप्रैल 2025 तक बाल्टीमोर, यूएसए में आयोजित हुआ। डॉ. रेखा जिवाने ने अपने शैक्षणिक पोस्टर ÷शरीर क्रिया विज्ञान में परावर्तक लेखन के प्रति विद्यार्थियों की धारणाएँ- शैक्षणिक और व्यावसायिक विकास की झलकियाँ÷ का प्रस्तुतीकरण किया। अपने प्रस्तुतीकरण में डॉ. जिवाने ने यह रेखांकित किया कि फिजियोलॉजी शिक्षा में रिफ्लेक्टिव राइटिंग (परावर्तनात्मक लेखन) को एकीकृत करने से मेडिकल छात्रों के सीखने के अनुभवों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। उन्होंने बताया कि यह नवाचार न केवल शैक्षणिक प्रदर्शन और अवधारण क्षमता को बेहतर बनाता है, बल्कि व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास को भी बढ़ावा देता है। उनके अनुसार, यह अभिनव दृष्टिकोण मेडिकल शिक्षा के एक समग्र मॉडल को प्रोत्साहित करता है, जिससे छात्र अधिक विचारशील, संलग्न एवं आजीवन सीखने वाले बनते हैं।

डॉ. रागिनी श्रीवास्तव ने पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) के प्रबंधन में योग अभ्यास और प्राकृतिक चिकित्सा की नैदानिक प्रभावशीलता विषय पर अपने शोध पोस्टर का प्रस्तुतीकरण किया। यह अध्ययन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा वित्तपोषित है। डॉ. श्रीवास्तव ने अपने शोध में यह महत्वपूर्ण तथ्य साझा किए कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम (PCOS) के प्रबंधन में प्रभावी पूरक चिकित्सा विधियाँ हैं। उनके निष्कर्षों के अनुसार, प्रतिभागियों में संपूर्ण स्वास्थ्य, हार्मोनल संतुलन, नींद की गुणवत्ता, चिंता में कमी तथा मासिक चक्र के नियमितीकरण में सुधार देखा गया।

इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रोफेसर (डॉ.) अजय सिंह ने कहा, डॉ. रेखा जिवाने एवं डॉ. रागिनी श्रीवास्तव द्वारा अमेरिकन फिजियोलॉजी समिट 2025 में प्रस्तुत शोध कार्य न केवल एम्स भोपाल की शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रतीक है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर हमारे संस्थान की पहचान को भी सशक्त बनाता है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हमारे फैकल्टी सदस्यों की भागीदारी और शोध प्रस्तुतियाँ निःसंदेह अन्य विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को भी उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान व नवाचार के लिए प्रेरित करेंगी। एम्स भोपाल अपनी अकादमिक व अनुसंधान गतिविधियों के माध्यम से चिकित्सा क्षेत्र में नई ऊँचाइयाँ प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह तीसरे केजीएमयू क्लबफुट कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित

भोपाल । एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह को किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू), लखनऊ में आयोजित प्रतिष्ठित तीसरे केजीएमयू क्लबफुट कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन क्योर इंटरनेशनल इंडिया ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश सरकार और केजीएमयू के बाल चिकित्सा आर्थोपेडिक्स विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इस कार्यक्रम में 146वीं चिकित्सा प्रशिक्षण सत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो पोन्सेटी विधि द्वारा क्लबफुट प्रबंधन पर आधारित था। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पोन्सेटी तकनीक की समझ और इसके व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया, जो क्लबफुट (जो एक सामान्य जन्मजात विकृति है) के सुधार के लिए एक विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त विधि है। एक दिवसीय सत्र में प्रमुख बाल चिकित्सा आर्थोपेडिक सर्जन, प्रशिक्षु और स्वास्थ्य पेशेवर एकत्र हुए, जो क्लबफुट से प्रभावित बच्चों के उपचार परिणामों में सुधार करने के लिए समर्पित हैं। अपने संबोधन में प्रो. सिंह ने आयोजक टीम के प्रयासों की सराहना की और प्रारंभिक निदान तथा निरंतर मानकीकृत उपचार पद्धतियों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने ऐसे भविष्य के निर्माण की दिशा में दिखाए गए समर्पण की प्रशंसा की जहां कोई भी बच्चा अनुपचारित क्लबफुट से पीड़ित न हो और कार्यक्रम के मिशन के अनुरूप ÷आज क्लबफुट का इलाज करें और क्लबफुट को इतिहास बनाएं÷ के लिए संस्थानों के बीच निरंतर सहयोग को प्रोत्साहित किया।

बाल विवाह रोकने जिले की समस्त परियोजनाओं में कंट्रोल रूम स्थापित

बाल विवाह करते पाये जाने पर दो साल की सजा व एक लाख रुपये का जुर्माने का प्रावधान

नरसिंहपुर। अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 को बाल विवाह रोकने के संबंध में राज्य शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इन्हीं निर्देशों के परिपालन में अक्षय तृतीया के अवसर पर जिले की समस्त परियोजनाओं में कंट्रोल रूम स्थापित किये गये हैं। अक्षय तृतीया 30 अप्रैल के तीन दिवस पूर्व 27 अप्रैल से क्रियाशील हो चुके हैं। जिले में बाल विवाह रोकने के लिए विकासखंड नरसिहपुर के अंतर्गत परियोजना अधिकारी श्रीमती पुष्पा मदकोरिया का मोबाइल नंबर 9340929496 व सहायक ग्रेड- 3 सुश्री श्वेता श्रीवास्तव का मोबाइल नंबर 8349871303, विकासखंड करेली व चांवरपाठा के अंतर्गत परियोजना अधिकारी श्री आदित्य मोहन पटेल का मेबाइल नंबर 9826541946, करेली के लिए सहायक ग्रेड 3 मो. वसीम कादरी का मोबाइल नंबर 9424994423 व चांवरपाठा के लिए सहायक ग्रेड 3 श्री रामकुमार पटेल का मोबाइल नंबर 7489097034, विकासखंड गोटेगांव के अंतर्गत परियोजना अधिकारी सुश्री रश्मि बोहरे का मोबाइल नंबर 9425860094 व सहायक ग्रेड- 3 कु. मानसी उपाध्याय का मोबाइल नंबर 8827087676 और विकासखंड चीचली व सांईखेड़ा के लिए परियोजना अधिकारी श्री उमा वर्मन का मोबाइल नंबर 9826539527, चीचली के लिए सहायक ग्रेड- 3 श्री शिखर तिवारी का मोबाइल नंबर 7987960866 व सांईखेड़ा के लिए सहायक ग्रेड- 3 श्री मदन मोहन शुक्ला का मोबाइल नंबर 7389899954 व 9479472785 पर सम्पर्क किया जा सकता है। जिले की सभी विकासखंड स्तर पर कहीं भी बाल विवाह रोकथाम की सूचना संबंधित टीम को मोबाइल नंबर पर दी जा सकती है। बालविवाह की सूचना मिलने पर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। बालविवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 अंतर्गत दो साल की सजा एवं एक लाख रूपये जुर्माने का प्रावधान है। यदि बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम एवं बालक की उम्र 21 वर्ष से कम है, तो यह शादी बालविवाह के अंतर्गत आती है। बाल विवाह में शामिल होने वाले घोड़े वाले, टेन्ट वाले, पालक, भाई, पंडित, घराती, बराती जो भी शामिल होगा, उन सभी पर कार्यवाही होगीं।

भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालसिंह आर्य की ग्वालियर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को लेकर प्रतिक्रिया

कांग्रेस ने संविधान के खिलाफ जाकर जनभावनाओं को कुचला, इसलिए बंद हुई दुकान

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालसिंह आर्य ने मीडिया से चर्चा के दौरान ग्वालियर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद इतने पाप किए हैं, इतना झूठ बोला है, देश की भावनाओं को बुरी तरह कुचला है और संविधान के इतने विपरीत चली है कि उसकी दुकान ही बंद हो गई है। आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस का संविधान हितैषी बनना हास्यास्पद है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र और भाजपा की राज्य सरकारों में संविधान और बाबा साहब के विचार पूरी तरह सुरक्षित है। कांग्रेस अपनी इस बंद दुकान को खोलने के लिए कोई न कोई षडयंत्र, हथकंडेबाजी लगातार कर रही है और उसकी संविधान बचाओ रैली भी ऐसी ही हथकंडेबाजी है।

संविधान के हिमायती थे, तो आपातकाल क्यों लगाया - भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालसिंह आर्य ने कहा कि कांग्रेस अचानक से संविधान बचाओ रैलियां कर रही है। मैं कांग्रेस के इन नेताओं से पूछना चाहता हूं क्या संविधान आज बना है? श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया संविधान 1950 में लागू हुआ था और इसमें हर व्यक्ति के लिए बराबर के अधिकार दिए गए हैं। कांग्रेस अगर संविधान का इतना ही सम्मान करती है, तो उसने एक साल बाद 1951 में ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार क्यों छीन लिया था? अगर वह संविधान की हिमायती है, तो बिना कारण से देश में आपातकाल लगाकर एक लाख निर्दोष लोगों को जेल में क्यों ठूंस दिया था? 1975 में न्यायालय और प्रेस के अधिकारों को क्यों बाधित कर दिया था? क्यों देश की जनता से आपातकाल के समय लिए गए निर्णयों को न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार छीना था?

कांग्रेस ने छीने दलितों के हक -भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालसिंह आर्य ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर संविधान की इतनी ही हितैषी थी, तो उसने संविधान दिवस क्यों नहीं मनाया? कांग्रेस के लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि क्यों कांग्रेस की सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाकर दलितों, आदिवासियों से आरक्षण का अधिकार छीना था? जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा देकर क्यों आरक्षण का प्रावधान समाप्त कर दिया था? काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को पं. नेहरू और इंदिरा गांधी की सरकारों ने क्यों ठंडे बस्ते में डालकर रखा? क्यों पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया? संविधान और दलित-आदिवासियों की हितैषी होने का ढोंग करने वाली कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने 1961 में आरक्षण के विरोध में मुख्यमंत्रियों को पत्र क्यों लिखा था और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने संसद में अपने भाषण में क्यों यह कहा था कि आरक्षण से बुद्धू पैदा होते हैं। वास्तव में कांग्रेस पार्टी संविधान के नाम पर झूठ बोलकर देश की जनता को बरगलाना चाहती है, उसे संविधान के सम्मान की कोई परवाह नहीं है।

स्वार्थ के लिए संविधान से खेलती रही कांग्रेस - अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालसिंह आर्य ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज संविधान को लेकर जो दिखावा कर रही है, उसकी वास्तविकता यह है कि उसने 88 बार से अधिक धारा 356 का दुरुपयोग करके चुनी हुई गैर कांग्रेसी सरकारों को अपदस्थ किया है। कांग्रेस की सरकारों ने 90 बार संविधान में संशोधन किए हैं। मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी है और देश का संविधान उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। कांग्रेस के नेताओं ने अपने हित के लिए संविधान का कई बार अपमान कर कुचला है। कांग्रेस पार्टी और उसके नेता अपने स्वार्थों के लिए संविधान से खेलते रहे, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जनता के हित के लिए संविधान में संशोधन किए। मुस्लिम बहनों को उनका हक देने के लिए मोदी सरकार ने तीन तलाक विरोधी कानून लागू किया, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस पार्टी ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं की, जो मोदी सरकार ने की है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार बचाने के लिए तो संविधान में संशोधन कर दिया, लेकिन गरीबों के कल्याण की योजना लाने के लिए कोई संशोधन नहीं किया।

22 लाख की इंगेजमेंट रिंग, जिसे ढूंढने आदिवासियों ने पार की हद

● 48 घंटे की अथाह मेहनत के बाद मिली अंगूठी, लौटी राजकुमारी की मुस्कान ● एमपी के आदिवासियों ने जीत लिया राजकुमारी का दिल, ईनाम भी नहीं लिया

भोपाल। कल्पना कीजिए एक अंगूठी की, जिसकी कीमत इतनी कि सुनकर आंखें फटी रह जाएं - पूरे 22 लाख रुपए! वो भी किसी आम इंसान की नहीं बल्कि चेक गणराज्य की राजकुमारी इटका क्लेट की सगाई की अंगूठी। सोचिए, उस अंगूठी का खो जाना कितना बड़ा सदमा होगा? और उसे खोजने के लिए जो मेहनत हुई, जो जुनून दिखा, वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। ये कहानी राजकुमारी की उस बेशकीमती अंगूठी की, तामिया के झरने की और उन आदिवासियों की जिन्होंने लाखों का इनाम ठुकराकर इंसानियत की मिसाल पेश की। राजकुमारी इटका क्लेट मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा आई थीं, अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए लेकिन कुदरत ने शायद उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। जब वह तामिया के मनमोहक छोटा महादेव झरने की शीतलता में डूबकर प्रकृति का आनंद ले रही थीं, तभी पलक झपकते ही वो हो गया जिसने उनकी दुनिया ही रोक दी। 22 लाख की वो अनमोल, भावनाओं से जुड़ी अंगूठी, फिसलकर झरने के अथाह पानी में समा गई। राजकुमारी के चेहरे की हंसी आंसुओं में बदल गई। उन्होंने तुरंत खोजने की कोशिश की, आस-पास के सैलानियों ने भी हाथ-पैर मारे, लेकिन झरने की गहराई और बहाव के आगे सब बेबस थे। छह घंटे

तक हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन 22 लाख का वो हीरा मानो पानी पी गया था। थक-हारकर, दिल पर पत्थर रखकर राजकुमारी को मायूस लौटना पड़ा। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। जहां उम्मीदें दम तोड़ रही थीं, वहीं छोटा महादेव पर नींबू पानी बेचकर गुजर बसर करने वाले मनोज विश्वकर्मा की आंखों में एक चिंगारी जली। उन्होंने तय किया - राजकुमारी मेहमान हैं, उनकी खोई हुई चीज हर हाल में वापस मिलेगी! मनोज ने आसपास के गांवों से आदिवासी युवकों को जुटाया। ऐसे युवक जिनकी रगों में मेहनत और ईमानदारी दौड़ती है। फिर शुरू हुआ संघर्ष, 22 लाख की अंगूठी पाने के लिए, एक दर्जन से ज़्यादा आदिवासी युवक दिन-रात एक करने पर तुल गए। झरने के पानी का बहाव तेज था लेकिन उनके हौसले के आगे सब फेल था। वो घंटों ठंडे पानी में खड़े रहते, हाथों से रेत निकालते, पत्तों के ढेर हटाते और उसे बारीक से छानते। एक-एक कंकर, एक-एक तिनका उनकी पैनी नज़रों से गुज़र रहा था। ये सिर्फ रेत छानना नहीं था, ये 22 लाख के उस खोए हुए विश्वास को वापस लाने की ज़िद थी। दिन बीता, रात आई, फिर अगला दिन... सूरज निकला, डूबा... लेकिन आदिवासियों के कदम नहीं रुके। उनकी कमर झुकी नहीं, उनके हाथ थमे नहीं। दो दिन तक लगातार, बिना थके, बिना रुके, उस लाखों की अंगूठी के लिए वो पानी में, रेत में, पत्थरों के बीच जूझते रहे। ये सिर्फ मेहनत नहीं थी, ये उस मेहमान के प्रति सम्मान था जिसका दर्द उन्होंने महसूस किया था। और फिर दो दिन की असहनीय मेहनत, घंटों पानी में खड़े रहने और लाखों बार रेत छानने के बाद वो क्षण आया जिसने सबकी आंखें नम कर दीं। रेत के ढेर के बीच, अचानक वो 22 लाख का हीरा जगमगा उठा! अंगूठी मिल गई थी! आदिवासियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत ये खुशखबरी राजकुमारी तक पहुंचाई।

भावुक होकर राजकुमारी देने लगी 5 लाख रुपए, किया इनकार- अंगूठी मिलने की खबर सुनते ही राजकुमारी इटका क्लेट की आंखों में आंसू आ गए, इस बार खुशी के! उन्होंने उन फरिश्तों से मिलने की इच्छा जताई जिन्होंने उनके लिए असंभव को संभव कर दिखाया था। जब राजकुमारी ने अपनी लाखों की अंगूठी वापस देखी, तो उनका हृदय भर आया। कृतज्ञता से भरकर उन्होंने उन मेहनती आदिवासियों को 5 लाख रुपए का भारी भरकम इनाम देने की पेशकश की। सोचिए, 5 लाख रुपए! किसी भी आम इंसान के लिए ये एक बहुत बड़ी रकम होती है। ये उनकी कई सालों की कमाई हो सकती थी। लेकिन उन महान आदिवासियों ने क्या किया? उन्होंने हाथ जोड़कर राजकुमारी की पेशकश ठुकरा दी! उनके शब्द सीधे दिल में उतर गए। मनोज ने कहा आप हमारी मेहमान हैं। हम आपके दर्द की कीमत नहीं लगा सकते। उन्होंने 5 लाख का इनाम लेने से साफ मना कर दिया! सिर्फ अपनी मेहनत की मजदूरी के तौर पर उन्होंने विनम्रतापूर्वक 41 हजार रुपए स्वीकार किए। इस घटना से अभिभूत होकर राजकुमारी इटका क्लेट भावुक हो गईं। उन्होंने कहा, 'भारत ने एक बार फिर मेरा दिल जीत लिया। यहां के लोग सिर्फ जमीन से नहीं, दिल से भी जुड़े हैं।' उन्होंने कहा कि वो इस अनुभव को कभी नहीं भूलेंगी।

॥ मंदिरम् ॥

95

नवलखा मंदिर, गुजरात

गुजरात, भारत का एक ऐसा राज्य है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन मंदिरों और अद्भुत स्थापत्य कला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इन्हीं रत्नों में से एक है नवलखा मंदिर, जो गुजरात के भावनगर जिले के घुमली गांव में स्थित है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सोलंकी वंश की स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना भी है। इस ब्लॉगपोस्ट में हम नवलखा मंदिर के इतिहास, वास्तुकला, धार्मिक महत्व और यात्रा से संबंधित जानकारी को विस्तार से जानेंगे। नवलखा मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में सोलंकी वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है और इसे गुजरात के सबसे बड़े सूर्य मंदिरों में से एक माना जाता है। मंदिर का नाम 'नवलखा' इसलिए पड़ा क्योंकि इसका निर्माण नौ लाख रुपये की लागत से हुआ था, जो उस समय एक विशाल राशि थी। सोलंकी वंश, जो गुजरात में 10वीं से 13वीं शताब्दी तक शासन करता था, अपनी उत्कृष्ट स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। नवलखा मंदिर इस वंश की समृद्धि और कला के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है। यह मंदिर बार्डा पहाड़ियों के बीच स्थित है, जो इसे प्राकृतिक सौंदर्य के साथ जोड़ता है।

कूनो में मादा चीता नीरवा बनी मां

5 शावकों को जन्मा

पांच शावकों के बाद भारत में हुए कुल 31 चीते

भोपाल। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रविवार को एक मादा चीता, नीरवा ने पांच शावकों को जन्म दिया। इससे नेशनल पार्क में चीतों की कुल संख्या 29 और भारत में 31 हो गई है। आपको बता दें कि चीता पुनर्वास परियोजना 2022 में शुरू हुई थी। यह भारत के लिए एक बड़ी सफलता है। नवंबर में, नीरवा ने चार शावकों को जन्म दिया था लेकिन उनमें से दो बाद में मर गए। हाल ही में, दो चीतों, प्रभाष और पावक को गांधी सागर अभयारण्य में छोड़ा गया। यह अभयारण्य नीमच और मंदसौर जिलों में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को अपने एक्स अकाउंट पर यह खबर साझा की। उन्होंने लिखा, यह बहुत खुशी की बात है कि कूनो नेशनल पार्क में चीतों की आबादी लगातार बढ़ रही है। हाल ही में, पांच साल की नीरवा ने पांच शावकों को जन्म दिया है। इन छोटे शावकों का आगमन चीता परियोजना की सफलता और भारत की समृद्ध जैव विविधता का प्रतीक है।

चीता पुनर्वास परियोजना भारत में 2022 में शुरू हुई थी। इस परियोजना के तहत, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाया गया था। भारत में चीते पहले विलुप्त हो गए थे। 17 सितंबर, 2022 को आठ नामीबियाई चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। इनमें पांच मादा और तीन नर थे। यह पहली बार था जब चीतों को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में ले जाया गया। फरवरी 2023 में, दक्षिण अफ्रीका से बारह और चीतों को कूनो लाया गया। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों को नए नाम भी दिए गए थे। ये नाम उनके नए घर के साथ जुड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 सितंबर, 2022 को 'मन की बात' में लोगों से चीतों के लिए नए नाम सुझाने को कहा था। इसके बाद पर्यावरण और वन मंत्रालय ने गुरुवार को नए नामों की घोषणा की। सरकार ने mygov.in प्लेटफॉर्म पर नामों के लिए प्रतियोगिता रखी थी। इसमें 11,565 लोगों ने भाग लिया। नामीबिया से आए चीतों के नाम अब धत्री, ज्वाला, नाभा और पवन होंगे। पहले इनके नाम तिब्लिसी, सियाया, सवाना और ओबन थे। दक्षिण अफ्रीका के चीतों के नाम उनके पुराने घरों के नाम पर थे। जैसे कि मापेसु, फिंडा, त्सवालु और वाटरबर्ग। अब इनके नए नाम होंगेः दक्ष, निर्वा, वायु, अग्नि, गामिनी, तेजस, वीर, सूरज, धीरा, उदय, प्रभास और पावक। पीएम मोदी ने पिछले साल 17 सितंबर को एक नामीबियाई चीते का नाम 'आशा' रखा था।

भोपाल में सड़क परिवहन का बनेगा समन्वित प्लान

सीएम बोले, जो भी कॉलोनी मंजूर हो, उसमें सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य करें

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भोपाल में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए जिम्मेदार अफसर एक समन्वित प्लान तैयार कराएं और उस पर अमल किया जाए। इसके साथ ही राजधानी में चोरी और आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर सतर्कता जरूरी है। इसलिए जो भी कॉलोनी स्वीकृत की जाए, उसमें सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य किया जाए। सीएम डॉ. यादव ने सोमवार को ये बातें राजधानी भोपाल के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान कहीं। उन्होंने प्रभारी मंत्री चैतन्य काश्यप, मंत्री कृष्णा गौर, विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा की मौजूदगी में मंत्रालय में भोपाल जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का भोपाल से बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने के लिए विधायक रामेश्वर शर्मा और अन्य जनप्रतिनिधियों ने आभार माना।

उन्होंने कहा कि इससे भोपाल में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों पर वाहनों की गति नियंत्रित रखने के साथ वाहनों की संख्या चक्काजाम जैसे हालात न बनने देने के हिसाब से होनी चाहिए। इसलिए अधिकारी और जनप्रतिनिधियों द्वारा राजधानी के सड़क परिवहन के संबंध में समन्वित रूप से प्लान बनाया जाए।

भोपाल शहर में आवागमन के लिए विकसित किए जाने वाली अधोसंरचना का निर्माण, मल्टीपरपज उपयोग की दृष्टि से किया जाए। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी कॉलोनी स्वीकृत हों उसमें सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य किया जाए। ऐसे में कॉलोनी में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। इसके साथ ही अन्य सभी कॉलोनियों में भी इसके लिए लोगों को प्रेरित करने का काम किया जाए।

कांग्रेस बोली-पुलिस पिट रही, अपराधी हंस रहे हैं

कमलापति स्टेशन पर पुलिसकर्मी से मारपीट, कहा-यही है डबल इंजन सरकार

भोपाल। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात शराब के नशे में युवकों ने जीआरपी जवान की पिटाई कर दी। युवक ने जवान की वर्दी फाड़ी और गालीगलौज की। यही नहीं आरोपी ने धार्मिक आधार पर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी कीं। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि दो अन्य की तलाश जारी है। इस मामले में भोपाल से लेकर दिल्ली तक राजनीति गरमाई हुई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से लेकर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत सहित तमाम विपक्षी नेता इस मामले में मप्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। शनिवार रात करीब 2 बजे भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन परिसर में शराब के नशे में युवकों ने जीआरपी जवान की पिटाई कर दी। उसकी वर्दी फाड़ दी। गालीगलौज की। धार्मिक आधार पर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी कीं। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार, शनिवार रात करीब 2 बजे जीआरपी बंसल वन की दुकानें और रेस्टोरेंट्स बंद कराने पहुंची थी। इसी दौरान कुछ युवक कार में बैठकर शराब पी रहे थे। पुलिस ने उन्हें हटने के लिए कहा तो युवक विवाद करने लगे। हाथापाई होने लगी।

आरोपी ने कॉन्स्टेबल से कहा- तुम हिन्दू भाई हो

युवकों ने हेड कॉन्स्टेबल नजर दौलत खान को पीटना शुरू कर दिया। जब हेड कॉन्स्टेबल संदीप और कमल रघुवंशी बचाने आए तो एक आरोपी ने कहा, तुम हिंदू भाई हो, हट जाओ। तभी एक अन्य आरोपी ने कहा, सब कहते हैं कि हिंदू भाई समझदार हैं, लेकिन ये (दौलत खान) लोगों को भाषण दे रहा था। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने आरोपियों का वीडियो बना लिया, जो रविवार को सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि तीन युवक जीआरपी की जीप का दरवाजा खोलकर पुलिसकर्मी की पिटाई कर रहे हैं। एएसआई रामदयाल ने बताया, इस मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मुख्य आरोपी जितेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके दो साथी फरार हैं।

गुंडे पुलिस पर हमला कर रहे सरकार तमाशा देख रही

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने एक्स पर लिखा- भोपाल रेलवे स्टेशन के बाहर गाड़ी में दारू पी रहे गुंडों ने जब कॉन्स्टेबल दौलत खान पर हमला किया, तो साथी कॉन्स्टेबल कमल को कहा 'तुम हिंदू भाई हो, हट जाओ।' शिवराज-मोदी राज ने प्रदेश में कानून नहीं, धर्म की पहचान को जिंदा किया है। गुंडे खुलेआम पुलिस पर हमला कर रहे हैं और सरकार तमाशा देख रही है। ये 'डबल इंजन' नहीं, 'डबल स्टैंडर्ड' की सरकार है।

2 मई को सभी जिलों में मनेगा लाड़ली लक्ष्मी उत्सव

एक पेड़ लाड़ली लक्ष्मी के नाम अभियान में होगा पौध-रोपण

भोपाल। मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना अन्तर्गत 2 मई 2025 को प्रदेश में 'लाड़ली लक्ष्मी उत्सव' जिला, नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायत पर उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा। इसमें स्थानीय प्रतिनिधि, लाड़ली बालिकाएं, उनके अभिभावक, लाड़ली क्लब की अध्यक्ष और सदस्य सक्रिय रूप से भाग लेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश सरकार की बेटियों के प्रति समर्पित सोच का प्रतीक है। हमारा लक्ष्य है कि हर बेटी को सम्मान, शिक्षा और आत्म-निर्भरता के अवसर प्राप्त हों। लाड़ली लक्ष्मी उत्सव एक नई ऊर्जा और विश्वास का संचार करेगा। उन्होंने प्रत्येक जिला और निकाय स्तर पर कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं, जिससे समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच और सशक्तिकरण का वातावरण तैयार हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी उत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रति साझा संकल्प है। लाड़ली लक्ष्मी उत्सव का संचालन स्वयं लाड़ली बालिकाओं द्वारा किया जाएगा। इसमें कन्या-पूजन, दीप प्रज्ज्वलन, लाड़ली बालिकाओं के प्रेरक उद्बोधन और 'अपराजिता' कार्यक्रम अंतर्गत मार्शल आर्ट का प्रदर्शन जैसे विशेष कार्यक्रम शामिल है। इस उत्सव के जरिये जिला, नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बेटियों के सम्मान और सशक्तिकरण का संदेश जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाली बालिकाओं तथा लाड़ली लक्ष्मी फ्रेंडली पंचायतों का सम्मान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 'एक पेड़ लाड़ली लक्ष्मी के नाम' अभियान में जन-प्रतिनिधियों और बालिकाओं द्वारा पौध-रोपण भी किया जाएगा। साथ ही लाड़ली बालिकाओं को आश्वासन प्रमाण-पत्र वितरित किये जायेंगे। कार्यक्रम में लाड़ली क्लब की सदस्य बालिकाएं अपने अनुभव भी साझा करेंगी।

कार्यकाल समाप्त, लेकिन डटे हैं साहब!

मप्र नाट्य विद्यालय के निदेशक टीकम जोशी का कार्यकाल समाप्त हो गया है लेकिन कार्यकाल में बढ़ोतरी की आशा में साहब अभी भी कुर्सी में डटे हैं। साहब का कुर्सी से मोह छूट नहीं रहा है। सूत्र बताते हैं कि निदेशक जोशी का तीन वर्षीय कार्यकाल विगत 17 अप्रैल

मोहन का मंत्रालय

आशीष चौधरी

2025 को समाप्त हो गया। कार्यकाल समाप्ति के पश्चात निदेशक बराबरा कार्यालय पधार रहे हैं और कामकाज निपटा भी रहे हैं। विद्यालय के पंजीयक ने पिछले दिनों एक पत्र संचालक संस्कृति को भेजा है जिसमें आगामी कार्यवाही से अवगत कराने का निवेदन किया गया है। जानकारों का कहना है कि आखिर निदेशक क्यों अभी तक डटे हैं? उनका कुर्सी मोह खत्म क्यों नहीं हो रहा है? संघ से नजदीकी की वजह से सरकार ने श्री जोशी को नवाजा है लेकिन वह संस्थान के लिए न्याय नहीं कर सके और विद्यालय की स्थिति जस की तस है। संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला का कहना है कि निदेशक श्री जोशी के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव है जो भी निर्णय होगा अवगत करा दिया जाएगा।

कप्तान की पोस्टिंग की चर्चा

राज्य शासन ने बीते दिनों एक नए जिले में कप्तान की पोस्टिंग की है। नए कप्तान ने पदस्थापना ग्रहण भी कर ली है लेकिन इसके पीछे चर्चाओं का दौर भी चल निकला है। सूत्र बताते हैं कि कप्तान साहब ने पोस्टिंग के लिए खासी मशक्कत और भेंट पूजा की है। भेंट पूजा कितनी की है इसका सही आंकलन सामने नहीं आ रहा है लेकिन पोस्टिंग के बाद साहब को संसाधन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। पोस्टिंग की वसूली कैसे होगी यह भी यक्ष प्रश्न है।

एसीएस को मिला नया कक्ष

राज्य शासन के एक विभाग के अपर मुख्य सचिव को आखिरकाल नया कक्ष मिल गया है। एसीएस पुराने भवन में ही अपना दरबार लगाए हुए थे लेकिन पिछले दिनों एक अपर मुख्य सचिव का कक्ष खोली होने पर उन्होंने कक्ष आवंटित करा लिया। अपर मुख्य सचिव ने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही व्हीआरएस ले लिया था। नया कक्ष मिलने से मंत्रालय में चर्चाओं का दौर है। अफसरों का कहना है कि उक्त कक्ष में अफसर अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाते हैं उससे पहले ही सर्विस से विदा ले लेते हैं। अपर मुख्य सचिव को कक्ष जरूर नया मिल गया है उससे जुड़े किस्से आज भी चर्चा में है। यह बात दीगर है कि साहब के नए कक्ष में बैठने से उनके मातहत अवश्य खुश है क्योंकि मातहत को इस गर्मी में पुराने भवन के गलियारों की गर्म हवाओं से मुक्ति मिल गयी है और नए भवन के वातानुकूलित भवन का आनंद मिल रहा है।

तहसीलदार का सेवा शुल्क

राजधानी की एक तहसील के तहसीलदार की कार्यप्रणाली से मातहत परेशान है। तहसीलदार किसी भी काम के मातहतों से सेवा शुल्क लिए बिना साइन नहीं करते हैं। तहसीलदार का कहना है कि तहसील क्षेत्र की जमीनें इतनी कीमती है कि उसका सौदा करने वालों से हजारों में सेवा शुल्क मिल सकता है तो आप (मातहत) खाली हाथ साइन कराने नहीं आया करे। ताजा मामला एक पत्रकार के रिश्तेदार के नामांतरण प्रकरण का था जिसमें तहसीलदार अनजाने में आदत की तरह सेवा शुल्क का गान करने लगा, तहसीलदार को नामांतरण कराने वाले के प्रभाव से अवगत भी कराया तो तहसीलदार का कहने लगा कि ऐसे दबाव आए दिन आते हैं? सेवा शुल्क जरूर लगेगा। तहसीलदार की सत्ता में अच्छी पैठ है, एक जनप्रतिनिधि के प्रति पूर्णत: आस्थावान तहसीलदार को आज तक कोई हटा नहीं सका है, जबकि तहसीलदार के रहते अभी तक तीन एसडीएम का तबादला हो गया है, लेकिन तहसीलदार जस की तस है। तहसीलदार एक ही दिन में कई दिनों की पेशी की आर्डर शीट लिखने के मामले में जांच का सामना भी कर रहे हैं।

ईडी के छापों से दहला आबकारी

प्रदेश के कई शहरों में ईडी के छापों से आबकारी विभाग दहल गया। विभाग के आला अधिकारी देर रात तक ईडी के छापों की जानकारी अखबारनवीसों से पूछते रहे और शराब कारोबारियों के नाम जानते रहे। एक सेवानिवृत्त अधिकारी तो छापों से बैचेन रहे। सूत्र बताते हैं कि ईडी ने कई शराब कारोबारियों के ठिकानों से दस्तावेजों के साथ डायरियां भी जप्त की है। डायरियों में किस किस के नाम है उन नामों के उजागर होने का इंतजार है। छापों ने परिवहन के बाद अब आबकारी की कार्यप्रणाली की पोल खोल दी है। फर्जी एफडी के बाद फर्जी चालान का खेल सालों से चल रहा है लेकिन विभाग के जिम्मेदार केवल समेटने में लगे है। सूत्रों का कहना है कि इन छापों से एक समूह को चिंताएं बढ़ गयी है। सरकार ने समूह को प्रमोट करने के लिए भरसक कोशिश की है और अब भी जारी है।

पेंशनरों ने केंद्र के समान 5 प्रतिशत डीआर मांगा

भोपाल। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश के पेंशनरों को केंद्र के समान 5 प्रतिशत देय तिथि से महंगाई राहत भुगतान करने की मांग की है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव वित्त को लिखे पत्र में जुलाई 24 से 3 प्रतिशत एवं जनवरी 2025 से दो प्रतिशत महंगाई राहत के आदेश शीघ्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि अधिनियम में डीआर देने के लिए छग से सहमति लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है एवं स्पष्ट किया कि 1 नवंबर 2000 से अभी तक मध्य प्रदेश एवं छग के महालेखाकार ने डीआर की राशि दोनों राज्यों से वसूल ही नहीं की है तो सहमति किस आधार पर ली जा रही है। संगठन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने कहा कि मध्य प्रदेश राज्य पुर्नगठन अधिनियम 2000 की धारा 49 अनुसूची 6 उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश के पेंशनरों को महंगाई राहत देने के लिए बाधक नहीं है।

भोपाल जिले के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने प्रदेश सरकार पर पेंशनरों को आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया।